



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2018

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रेसोरसिनोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 14/37/2016 डीजीएडी.—1. मेसर्स अतुल लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य और जापान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत करने और पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/37/2016-डीजीएडी द्वारा अधिसूचना जारी की, जिसमें पाटन-रोधी नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की गई, ताकि चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (1) प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत आवेदक से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल का पाटन होने का आरोप लगाया गया है।
- (2) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को पाटन-रोधी आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया है।
- (3) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
- (4) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित कर दिया था कि वह संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
- (5) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और दूतावासों को आवेदन-पत्र की अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति प्रदान की है।
- (6) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-
 - (1) मेसर्ज शंघाई अमीनो-केम टीएम कंपनी लिमिटेड
 - (2) मेसर्ज सुमिटोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड
- (7) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों और उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
 - (1) मेसर्ज सुमिटोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड, जापान
 - (2) मेसर्ज ईस्ट वेस्ट कापेरिशन, जापान
 - (3) मेसर्ज सुमीकट केमटेक्स कंपनी लिमिटेड, जापान
 - (4) मेसर्ज बी. आर. केमिकल्स, जापान
 - (5) मेसर्ज ईनाबाटा एंड कंपनी लिमिटेड, जापान
 - (6) मेसर्ज झेझियांग होंगशेंग, चीन जनवादी गणराज्य
 - (7) मेसर्ज अमीनो कैम (एचके) कंपनी लिमिटेड, होंगकॉंग
- (8) बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) की प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे प्राधिकारी को संबद्ध सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान कर दें। लेकिन किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने एमईटी का दावा नहीं किया है।
- (9) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-
 - (1) मेसर्ज ब्लेक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
 - (2) मेसर्ज भीजराज काप्मलेक्स, मुंबई
 - (3) मेसर्ज शीतल केमिकल्स, हैदराबाद
 - (4) मेसर्ज सिंह प्लास्टिसाईजर्स एंड रेसिन्स (आई) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
 - (5) मेसर्ज टेक्नो वास्केम, कोलकाता
 - (6) मेसर्ज राजशा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, वडोदरा
 - (7) मेसर्ज एशियाटिक कलर केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद

- (8) मेसर्ज शोधाना लबरोटरीज, हैदराबाद
- (9) मेसर्ज एसआरएफ लिमिटेड, नई दिल्ली
- (10) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
- (1) मेसर्ज ब्लेक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
- (2) मेसर्ज टेक्नो वास्केम, कोलकाता
- (3) मेसर्ज राजशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा
- (4) मेसर्ज एसआरएफ लिमिटेड, नई दिल्ली
- (11) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय वृत्तान्त सार्वजनिक फाईल के रूप में नियम 6(7) के अनुसार खुला उपलब्ध कराया है, ताकि हितबद्ध पक्षकार उनकी जांच कर सकें।
- (12) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने की व्यवस्था करें। इसलिए वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है तथा परिकलन और आवश्यक विश्लेषण करने के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विस्तृत सूचना प्रदान की गई है।
- (13) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उन्हें निर्मित करने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत का आकलन किया गया है, ताकि क्षति मार्जिन का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (14) इसके अतिरिक्त जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई है। इस जांच के प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक समझा गया है, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया गया है।
- (15) प्राधिकारी ने अनुबंध-3 में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर जितना संभव था, घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है, ताकि भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत आकलित की जा सके जिससे यह पता लग सके क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (16) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उसे सार्वजनिक फाईल में रखा गया था।
- (17) जांच 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 (जांच अवधि) तक की अवधि के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 तथा जांच अवधि को भी शामिल किया गया है।
- (18) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए 31 अक्टूबर, 2017 को सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में 8 नवंबर, 2017 तक और उनके प्रत्युत्तर 15 नवंबर, 2017 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें।
- (19) अंतिम जांच परिणाम जारी करने की तारीख 12 अक्टूबर, 2017 थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 17 (1) (क) के अनुसार इसे तीन महीनों के लिए अर्थात् 12 जनवरी, 2016 तक बढ़ा दिया था।
- (20) 07.12.2017 को प्रकटन विवरण जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अत्यावश्यक तथ्य

निहित हैं। पक्षकारों से कहा गया था कि यदि वे उस पर अपनी कोई टिप्पणी देना चाहते हैं, तो उसे 14.12.2017 तक प्रस्तुत कर दें। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण पश्चात प्राप्त हुई टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।

- (21) इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों का निदान किया गया है।
- (22) जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने न तो प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत किया है और न ही इस जांच से संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी माना गया है।
- (23) इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा *** सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।
- (24) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 65.91 रूपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग के निवेदन

4. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग के अनुसार उसके द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं।
- (2) याचिकादाता सल्फोनेशन-फ्यूजन प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है। मेसर्स अतुल लिमिटेड की उत्पादन प्रक्रिया, जांच में भाग लेने वाले अन्य उत्पादकों की तुलना में वास्तव में तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अधिक कुशल है। इसको सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई के प्रोफेसर एम. एम. शर्मा का एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि मेसर्स आरती लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी अत्यधिक कुशल और लागत प्रभावी है क्योंकि यह एक संघटित प्रक्रिया है और उप-उत्पाद उचित कीमतों पर बेचे जाने योग्य हैं। हाईड्रोपेरोक्सिडेशन और एमपीडीए हाईड्रोलाईसिस जैसी अन्य प्रक्रिया की तुलना में सल्फोनेशन अधिक स्थिर और सुरक्षित है। हाईड्रोपेरोक्सिडेशन नामक अन्य प्रक्रिया खतरनाक है और वर्ष 2012 में मितसुई केमिकल्स में एक घातक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण उसे अपना रिसोर्सिनोल के विनिर्माण संयंत्र को बंद करना पड़ा था, जो कि तब से बंद पड़ा है। एमपीडीए हाईड्रोलाईसिस प्रक्रिया बहुत महंगी है, जिस पर अधिक पूंजी लागत आती है और यह बड़ी मात्रा में उत्सर्जन सृजित करती है, जिससे उत्पाद की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। तथापि, उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की कोई योग्यता नहीं है क्योंकि पाटन-रोधी विधि में उत्पादन प्रक्रिया एक प्रासंगिक कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया जाता है कि किसी भी पूर्व जांच में प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद की पहचान करते समय एक निर्धारक कारक के रूप में उत्पादन प्रक्रिया पर कभी भी विचार नहीं किया गया है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग और जापान के उत्पादक द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया पूर्णतया भिन्न है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी भिन्न है, व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य है और यह व्यापक रूप से प्रकाशित है। वर्ष 1914 के बाद से विश्वभर में सभी ऐसे अन्य संयंत्र बंद हो गए हैं, जो कि रिसोर्सिनोल का उत्पादन करने के लिए बेनजेनेडिसल्फोनेशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि यह प्रौद्योगिकी खर्चीली है।
- (2) सुमिटोमो की उत्पादन प्रक्रिया हाईड्रोपेरोक्सिडेशन है, जिसका मुख्य कच्चा माल बेनजीन और प्रोपलीन है। ऐसीटोन एक ऐसा उप-उत्पाद है, जो कि इस प्रक्रिया में उत्पादित होता है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया बेनजेनेडिसल्फोनेशन है, जिसका मुख्य कच्चा माल बेनजीन, कॉस्टिक सोडा और ओलियम (सल्फेरिक एसिड) है। इस प्रक्रिया का मुख्या उप-उत्पाद रेसो-टर, सोडियम 2 सल्फाईट और सोडियम सल्फेट है। कच्चे माल में भिन्नता

होने के फलस्वरूप बेनजेनेडिसल्फोनेशन प्रोद्योगिकी और हाईड्रोपेरोक्सीडेशन प्रोद्योगिकी के बीच उत्पादन की लागत में अंतर होता है। निर्यातक की तुलना में याचिकादाता की प्रक्रिया से कम लाभ होता है।

- (3) याचिकादाता बेनजेनेडिसल्फोनेशन प्रक्रिया से रेसोरसिनोल विनिर्मित करता है, जो कि लागत प्रभावी नहीं है और इसके कारण याचिकादाता को क्षति हो रही है क्योंकि इसे निरंतर अद्यतन बनाए रखने की आवश्यकता होती, जिससे कंपनी के संसाधनों में पर्याप्त रूप से कमी आती है। यह प्रक्रिया 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है और उद्योग में पुरानी प्रक्रिया होने के कारण रेसोरसिनोल का विनिर्माण करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रोद्योगिकियों और प्रक्रियाओं की तुलना में इससे उत्पादन की लागत अधिक आती है।
- (4) याचिकादाता रेसोरसिनोल विनिर्मित करने के लिए सल्फोनेशन प्रक्रिया प्रयुक्त करता है। यह प्रक्रिया महंगी है और रेसोरसिनोल के उप-उत्पाद को आसानी से वाणिज्यिक रूप से नहीं बेचा जा सकता है और यह पूर्णतया अपव्यय है। ऐसा कहा जाता है कि याचिकादाता बैच-प्रक्रिया द्वारा उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया में पूर्णतया स्वचालित सतत प्रक्रिया प्रयुक्त करके संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में अपेक्षित जनशक्ति से अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है और यह कम कुशल है। उनके विशेषज्ञ द्वारा इस पर भी अधिक बल दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त की जा रही प्रोद्योगिकी पुरानी है, जो कि उसकी क्षति और घाटों का प्रमुख कारण है।
- (5) इससे पहले कोपर क्लेड लेमिनेट्स के आयातों के खिलाफ पाटन-रोधी जांच के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रोद्योगिकी पुरानी और महंगी है तथा अनेक असंबद्ध कारणों से यह अपनी विनिर्माण सुविधाओं को उन्नत नहीं बना पाया है। प्रोद्योगिकी में विकास को नहीं अपना पाना, घरेलू उद्योग की क्षति का प्रमुख कारक है। प्राधिकारी ने निष्कर्ष दिया था कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि पाटित आयातों से भिन्न अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद “रेसोरसिनोल” है। इसे रेसोरीन मेटा-डिहायोरेक्सी, 1, 3 डिहायोरेक्सी अथवा 1, 3 बेनजेनीडियोल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा क्रिस्टल्लेईन, ऐरोमेटिक, हाईग्रोस्कोपिक और सफेद ठोस उत्पाद है जो कि जल में समाधेय हो जाता है और व्युत्पन्न करने के लिए बहुत सहायक है।

7. संबद्ध वस्तुओं को अनेक उद्योग द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि रबड़ उद्योग में सामग्री और रबड़ के बीच प्रवर्तक के रूप में, प्रसाधन सामग्री तैयार करने में इसे एंटीसेप्टिक तत्वों के रूप में, विशेषीकृत थर्मोसेटिंग लकड़ी के चिचिपाहट वाले रेसिन्स के रूप में, विभिन्न प्लास्टिक सामग्री में प्रयुक्त होने वाले हाईड्रोक्सिबेनजोफेनोन किस्म के अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स आदि में इसे इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार ऐसा दावा किया है कि “रेसोरसिनोल” की 60% से भी अधिक मांग टायरों सहित रबड़ के उत्पादों के लिए चिपचिपे रेसिन के लिए है।

8. उत्पादन प्रक्रिया में अंतर होने के संबंध में प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और यह नोट किया है कि जापान, चीन और भारत में उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तीनों विनिर्माण प्रक्रियाओं के फलस्वरूप समान उत्पाद उत्पादित होते हैं, जिनके समान विनिर्देशन, बाजार में समान ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि वर्तमान जांच के परिणाम के लिए उत्पादन प्रक्रिया की विशिष्टता प्रासंगिक नहीं है। इसके अतिरिक्त ओटोमेटिव टायर मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट ने यह निर्णय दिया था कि—

“यह निवेदन कि आयातित वस्तुएं भिन्न प्रक्रिया से विनिर्मित होती हैं और यह तर्क कि आयातित वस्तुएं गुणवत्ता में भिन्न होती हैं, जांच परिणाम को अमान्य नहीं ठहराती हैं। पाटन-रोधी विधि के अंतर्गत विनिर्माण की प्रक्रिया प्रासंगिक नहीं है। गुणवत्ता में अंतर भी कोई मायने नहीं रखता है। आयातित वस्तुओं और देश में उत्पादित वस्तुओं का समान उपयोग है और उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सटीक रूप से “समान वस्तु” माना गया है। इन तथ्यों और परिस्थितियों में इन अपीलों में किए गए निवेदन की कोई योग्यता नहीं है। अपीलें असफल होती हैं और उन्हें खारिज किया जाता है।”

9. संबद्ध वस्तुओं को टैरिफ के अध्याय शीर्ष 29072100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, याचिकादाता द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात अन्य टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत भी किए जा रहे हैं। इसलिए प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि एचएस संहिता केवल निर्देशात्मक है और सभी परिस्थितियों में उत्पाद का विवरण प्रचलित रहेगा।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। नियमावली के अनुसार उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं, समान वस्तुएं हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित दायरे और परिभाषा के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है और यह पाटन-रोधी नियमावली के भीतर समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

11. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र अकेला उत्पादक है, इसलिए नियमावली के अनुसार याचिकादाता अकेला संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है। याचिकादाता का पर्याप्त आधार है और वह नियमावली की परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है।
- (2) इन मुद्दों के संबंध में कि घरेलू उद्योग का चीन में व्यापारी/निर्यातक के साथ संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि चीन में संबंधित प्रयोज्यता संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन/निर्यात नहीं कर रहा है। इसलिए याचिकादाता ने नियमावली के अंतर्गत भी इस तथ्य की घोषणा नहीं की है कि क्योंकि उसमें ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि ऐसे सभी प्रयोज्यताओं के बारे में घोषणा की जाए जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन/निर्यात नहीं कर रहे हैं।
- (3) याचिकाकर्ता ने विषय देश से आयात किया है, लेकिन पीओआई से पहले और बाद में गैर-विषयक देश से 1-3 साइक्लोहेक्सानिडियो (1,3-सीएचडी) के निर्यात के लिए झूठी फ्री लाइसेंस के लिए आयात किया गया है, जिसके लिए कंपनी पूरी तरह से उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से पात्र है।
- (4) जांच अवधि के दौरान याचिकादाता ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। याचिकादाता संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है। इस प्रकार याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और 5 (3) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

12. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) क्षति अवधि के दौरान याचिकादाता ने आयात किए हैं। याचिकादाता ने जांच अवधि के बाद मात्र दो सप्ताहों में विचाराधीन उत्पाद के आयात किए हैं। इससे याचिकादाता के ऐसे आचरण के पैटर्न का स्पष्ट पता चलता है कि वह घरेलू बाजार में अपर्याप्त आपूर्ति को पूरा करने के लिए विचाराधीन उत्पाद का निरंतर आयात कर रहा है।
- (2) याचिकादाता के आयात (जैसा कि दावा किया गया है "केप्टिव खपत" के लिए है) स्पष्टतया केप्टिव खपत के लिए नहीं थे चूंकि उसने रिसोरीनोल के निचले स्तर के उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की थी।
- (3) घरेलू उद्योग की चीन में मेसर्ज अतुल चाईना लिमिटेड नामक एक संबंधित कंपनी है। यह एक व्यापारी कंपनी है और आयात-निर्यात कारने में लगी हुई है। जांच शुरू किए जाने के समय याचिकादाता प्राधिकारी को इस तथ्य को प्रकट करने में विफल रहा है और याचिका में झूठी घोषणा की है कि वह किसी विदेशी प्रयोज्यता अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

13. वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र मेसर्ज अतुल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन उत्पाद का अकेला घरेलू उत्पादक है और जिसने चीन जनवादी गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के

मामले में जांच के लिए विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के चरण में यह निर्धारित किया था कि याचिकादाता जो कि संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है, नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग के आधारकी अपेक्षाओं को पूरा करता है और नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर याचिकादाता घरेलू उद्योग बनता है।

14. घरेलू उद्योग द्वारा आयात किए जाने के संबंध में प्राधिकरण का कहना है कि गैर-विषयक देश से आयात किया गया है। डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता और क्षमता के लिए, घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान 1-3-सीएचडी का उत्पादन किया है जो कि खातों की पुस्तकों से विधिवत सत्यापित किया गया था।

15. अकेले याचिकादाता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 100% भाग बनता है। तदनुसार, कानूनी प्रावधानों और मामले के तथ्यों की सावधानी पूर्वक जांच करने पर प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर पात्र घरेलू उद्योग बनता है और आवेदक उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता संबंधी मुद्दे

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

16. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाता ने केवल ऐसी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है, जिसकी गोपनीयता की अनुमति, नियमावली के अंतर्गत और प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार दी गई है।
- (2) याचिकादाता ने आवेदन-पत्र के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त प्रदान किए हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी भी विशिष्ट सूचना का उल्लेख नहीं किया है, जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है और ऐसी गोपनीयता नियमावली के अंतर्गत यथोचित नहीं है।
- (3) भारत को निर्यात की मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्रयों की सकल मात्रा, उत्पादन बिक्रियां और भारत को निर्यातों के लिए औसत कीमत जैसी सूचना सूचीबद्ध वृत्तान्त में प्रदान की गई है क्योंकि ऐसी सूचना व्यवसाय के स्वामित्व संबंधी सूचना है।
- (4) किसी भी निर्यातक ने ऐसा कोई अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि गोपनीय वृत्तान्त की सही प्रतिकृति हो। उन्होंने मात्रा संबंधित समस्त सूचना को गोपनीय रखा है। साथ ही उन्होंने गोपनीयता के दावे का भी कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उनके उत्तर, निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय वृत्तान्त को प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का नितांत उल्लंघन है। इसलिए हमारा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे ऐसे हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों की अनदेखी करें और साथ ही निर्यातकों के उत्तरों को भी खारिज कर दें और उन्हें विशिष्ट पृथक निरूपण से भी वंचित करें।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

17. वर्तमान जांच की कार्यवाई के दौरान गोपनीयता के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिका में अत्यंत गोपनीयता बना कर रखी गई है। याचिका में मात्रा से संबंधित भी कोई सूचना निहित नहीं है।
- (2) याचिकादाता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जो कि हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां देने से रोकती है। याचिका में क्षमता संबंधी आंकड़े भी स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका प्रकटन नहीं किए जाने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। याचिका का अगोपनीय वृत्तान्त भी विकट रूप से अपर्याप्त है। यह प्राकृतिक न्याय का सीधा उल्लंघन है। याचिकादाता ने निम्नोक्त के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है:-
 - (क) क्षमता, क्षमता उपयोग।
 - (ख) सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत।
 - (ग) प्रपत्र - क - कच्चा माल और पैकेजिंग सामग्री की खपत।
 - (घ) प्रपत्र - ख - कच्चे माल की खपत के मानदंड और वास्तविक खपत के साथ तुलना।
 - (ङ) प्रपत्र - ग 1 - ग 2 - विभिन्न व्यय का विवरण।

(च) प्रपत्र - घ - खपत और उपयोगिताएं।

(छ) प्रपत्र - ड - बिक्रियों की वसूली का विवरण।

(3) याचिका में क्षमता के आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रकटन के लिए कोई यथोचित कारण नहीं बताया गया है। नियमों का ऐसा उल्लंघन, पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 6.5 की भी अपवचना है और उसे तुरंत आशोधित किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. नियम 6 (7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है, जिसमें जांच के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय वृत्तान्त निहित है।

19. वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के गोपनीयता के दावों की प्राधिकारी द्वारा उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी दायर करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

20. हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना की गोपनीयता के बारे में तर्क दिए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे, प्राधिकारी द्वारा सामान्यतया अपनाई जा रही पद्धति से सुसंगत हैं। जहां कहीं भी संभव हुआ है, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त प्रदान किया गया है। घरेलू उद्योग ने गोपनीय याचिका में निहित उसकी विभिन्न सूचनाओं का सूचीबद्ध वृत्तान्त प्रदान किया है।

ड. विविध मुद्दे

घरेलू उद्योग के निवेदन

21. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) प्राधिकारी को चीन के निर्यातकों के उत्तर को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सही और प्रमाणित सूचना प्रस्तुत करने के अपने दायित्व को निभाने में विफल रहे हैं। चीन से प्रतिवादी उत्पादकों ने चीन की सरकार से उनको प्राप्त हुई आर्थिक सहायता से संबंधित किसी भी सूचना को सुगमता से छोड़ दिया है, जो कि कम कीमत के चीन के आयातों का एक प्रमुख कारण है।
- (2) घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी बहुत कुशल है। इसके अतिरिक्त उसने अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए एक पत्र भी प्रस्तुत किया है। आयातक और निर्यातक केवल प्राधिकारी के मस्तिष्क में पूर्वग्रह पैदा करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
- (3) क्षमता विस्तार के संबंध में यह निवेदन है कि यह दीर्घकालिक निर्णय है और इन्हें देश में मांग को ध्यान में रख कर लिया गया है।
- (4) घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, भारत में आयातित किसी भी वस्तु के समान है। इसके अतिरिक्त वे अनेक उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर रहे हैं और कभी भी किसी ने भी उनकी विश्वसनीयता के प्रति कोई प्रश्न नहीं उठाया है। किसी भी स्थिति में किसी भी संबंधित पक्षकार ने साक्ष्यों के साथ अपने दावे को पूर्णतया प्रमाणित नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी को इन निराधार दावों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- (5) यह आरोप गलत और निराधार है कि संयंत्र नियमित रूप से बंद रहते हैं।
- (6) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय याचिकादाता को उपलब्ध ऐसी श्रेष्ठ सूचना के आधार पर अपने मामले को सिद्ध करना अपेक्षित होता है, जो कि प्रथम दृष्टया प्राधिकारी को जांच शुरू करने के लिए संतुष्ट कर सके। जांच शुरू करने के बाद प्राधिकारी, घरेलू उद्योग, सहयोगी निर्यातकों द्वारा दी गई अथवा किसी भी अन्य स्रोत से एकत्रित की गई सूचना पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त जांच शुरू करने के लिए प्राधिकारी को नियम 5 (3) के

अंतर्गत केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है। तथापि, याचिकादाता ने याचिका को प्रस्तुत करने के लिए अधिकारिक रूप से आयात के आंकड़े एकत्र किए हैं और उन्हें प्रयुक्त किया है। आयात के आंकड़ों को एकत्र करने का स्रोत भी सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया है और इसलिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार को कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है।

- (7) विषय देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल नहीं करने के संबंध में, यह कहा गया है कि अमरीका से अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस मार्ग के तहत हैं, जो कि एक अलग उत्पाद के उत्पादन के लिए 1,3 सीएचडी है जो निर्यात किया जाता है। इसलिए, अंततः ये माल वाणिज्य की मुख्य धारा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं इसके अलावा, कंपनी पहले से ही जागरूक थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी पर्यावरण और अन्य निहित मुद्दों के कारण अपने कार्यों को बंद करने वाली थी और यह उचित महसूस करती थी कि अमरीका को एंटी डंपिंग जांच की याचिका में शामिल नहीं करना चाहिए।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

22. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) एक ऐसे अकुशल घरेलू उद्योग को बचाने को ओट में पाटन-रोधी शुल्क लागू करना जन हित में नहीं होगा, जिसने भारत में उच्चतर कीमतों पर अपने उत्पादों के बेचने के लिए प्रोद्योगिकी का उन्नयन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है।
- (2) ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिससे पाटन-रोधी जांच शुरू करने की स्थिति प्रमाणित हो सके। प्राधिकारी ने उचित रूप से और संबंधित तथ्यों की पर्याप्त संवीक्षा करके जांच शुरू नहीं की है। इसमें कानूनी और वास्तविक आधार की कमी है।
- (3) अप्रचलित प्रोद्योगिकी के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और इसलिए उसकी लागत बहुत अधिक आ रही है।
- (4) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसके अतिरिक्त वह विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता भी नहीं है। याचिकादाता अनुरोध किए गए आदेशों के प्रति भी सक्रिय नहीं है जिसके कारण उसने रिसोर्सिनोल की नियमित आपूर्ति के लिए आयातित स्टॉक पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। याचिकादाता बाजार में विश्वसनीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने में असमर्थ है जिसके फलस्वरूप उसे वैकल्पिक स्रोतों से खरीदारियां करनी पड़ी हैं। एक ऐसी अकुशल कंपनी को बचाने को ओट में पाटन-रोधी शुल्क लागू करना जन हित में नहीं होगा, जिसने भारत में उच्चतर कीमतों पर अपने उत्पादों के बेचने के लिए प्रोद्योगिकी का उन्नयन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। प्राधिकारी को इस मुद्दे का निदान करते समय इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।
- (5) घरेलू उद्योग ने द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए गए आयात के आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को अपनी जांच का आधार बनाया है और इसलिए स्वतः जांच शुरू करने का आधार गलत है।
- (6) संयुक्त राज्य अमरीका से कुल आयातों के 3% से भी अधिक आयात होने के बावजूद भी उसे संबद्ध देश नहीं बनाया गया है। याचिकादाता ने संयुक्त राज्य अमरीका से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं और संयुक्त राज्य अमरीका से याचिकादाता द्वारा किए गए आयातों की मात्रा बहुत अधिक है। संयुक्त राज्य अमरीकी की व्यापारिक बिक्री, देश में कुल आयातों के 1.24% से भी कम है, जो कि समग्र रूप से अप्रासंगिक है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका को बाहर रखने के प्रयास स्वरूप याचिकादाता द्वारा प्रयुक्त व्यापारिक बिक्रियों का अभिप्राय नितांत भ्रामक है, क्योंकि अन्यथा याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत वर्तमान याचिका को दायर करने के लिए पात्र नहीं होता। इसके अतिरिक्त वर्तमान जांच शुरू करने के 291 दिनों (9.7 महीनों में) के बाद हाल ही में अर्थात् जुलाई, 2017 में याचिकादाता के संयंत्र ने उत्पादन करना बंद कर दिया है। इस प्रकार इस याचिका पर विचार करने और जांच शुरू करने में प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समय लिया गया है।
- (7) जैसा कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार की मांग को पूरा नहीं कर सकता है, एंटी डंपिंग शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम इंडियन इंडस्ट्रीज के बड़े हित में नहीं होगा।
- (8) रिसोर्सिनोल के उत्पादकों का इरादा न तो पाटन करने का है और न ही उन्होंने भारत में निर्यात बढ़ाने के लिए पाटन को एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विशिष्ट निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) प्रतिवादी पक्षकारों के इस आशय के निवेदनों के संबंध में कि भारतीय उद्योग द्वारा अप्रचलित और प्रदूषण पैदा करने वाली प्रोद्योगिकी प्रयुक्त की जा रही है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग वास्तव में एक भिन्न प्रोद्योगिकी प्रयुक्त कर रहा है। तथापि, उसने आवश्यक प्रदूषण अनुमति प्राप्त की है और वह 10 वर्षों से भी अधिक समय से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा प्रमाणित नहीं किया है अथवा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उनका यह प्रमाणित हो सके कि भारतीय उद्योग द्वारा प्रयुक्त की जा रही प्रोद्योगिकी लागत प्रभावी नहीं है। इसके अतिरिक्त मात्र इस कारणवश कि भिन्न पक्षकार भिन्न प्रोद्योगिकी प्रयुक्त कर रहे हैं, जो कि अधिक अथवा कम लागत प्रभावी हो सकती है, किसी पक्षकार के लिए यह कारण नहीं हो जाता है कि वह पाटन करने लगे। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी प्रतिवादी पक्षकारों के दावे में कोई गुण (मेरिट) नहीं पाते हैं।
- (2) घरेलू उद्योग ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है और ग्राहकों को उनकी गुणवत्ता स्वीकार्य है। यह भी नोट किया जाता है कि भारत में उसके ग्राहकों का सुदृढ़ आधार है, जो यह प्रमाणित करता है कि उसकी वस्तुएं आयातित वस्तुओं के समान हैं। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो अपने दावे को सिद्ध किया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे उनका यह दावा सिद्ध हो सके कि घरेलू उद्योग की वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है अथवा स्वीकार्य नहीं है। गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क में स्वतः गुणवत्ता कोई मुद्दा नहीं है।
- (3) क्षमता विस्तार एक दीर्घकालिक निर्णय है जो कि समग्र मांग और मद की अर्थव्यवस्था के आधार पर लिया गया है। तथापि, कोई भी प्रस्तावित क्षमता विस्तार का इस मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- (4) जन हित के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क का प्रयोजन, उचित व्यापार सुनिश्चित करना और घरेलू उद्योग को व्यापार करने का समान क्षेत्र प्रदान करना है। ये व्यापार को प्रतिबंधित करने अथवा उत्पादों की लागत में अनुचित वृद्धि करने के उपाय नहीं हैं।
- (5) घरेलू उद्योग के इस आरोप के संबंध में कि चीन के प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने दावे को सिद्ध नहीं किया है।
- (6) वर्तमान जांच में संयुक्त राज्य अमेरिका के गैर-समावेश को संबोधित में यह नोट किया गया है कि जांच के आरंभ होने के समय प्राधिकरण द्वारा इस तथ्य की जांच की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से विषय वस्तु का आयात कुल आयात का लगभग 4.5% था, हालांकि, इसका अधिकांश निर्यात निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंस के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा आयात किया गया था। चूंकि वे भारत में मर्चेट की बिक्री के लिए नहीं थे, इसलिए घरेलू उद्योग में डंपिंग और संबंधित चोट के कारण ऐसा नहीं हो सकता था।
- (7) इस आरोप के संबंध में कि गलत आधार पर जांच शुरू की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की गई है। पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई विधि नहीं है कि घरेलू उद्योग अपने आवेदन-पत्र में अपना विश्लेषण द्वितीय स्रोतों के आंकड़ों, उदाहरणतः आईबीआईएस, इन्फोव्हाइव आदि के आधार पर विश्लेषण नहीं कर सकता है। जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से कारोबार-वार आयात के आंकड़े मंगाए हैं और डीजीसीआईएंडएस के आयात के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारणसामान्य मूल्य

24. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और उन्हें सलाह दी थी कि वे निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से सूचना प्रदान करें। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

- (1) मेसर्स झेझियांग होंगशेंग, चीन जनवादी गणराज्य
- (2) मेसर्स अमीनो केम (एचके) कंपनी लिमिटेड, होंगकॉंग

- (3) मेसर्ज सुमिटोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड, जापान
- (4) मेसर्ज ईस्ट वेस्ट कार्पोरेशन, जापान
- (5) मेसर्ज सुमलकेट केमटेक्स कंपनी लिमिटेड, जापान
- (6) मेसर्ज बी. आर. केमिकल्स, जापान
- (7) मेसर्ज इनाबाटा एंड कंपनी लिमिटेड, जापान

घरेलू उद्योग के विचार

25. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में सूचना प्रस्तुत की थी, जो कि जांच शुरू करने के लिए आवश्यक थी। नियम 5 के अनुसार घरेलू उद्योग को ऐसी सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो कि जांच शुरू करने को यथोचित ठहराने के लिए पर्याप्त है। उसने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के समर्थन में भी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- (2) यदि घरेलू उद्योग के पास उचित रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर और निर्दिष्ट प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार संरक्षण के सिद्धांत को लागू करने के बाद संरचित सामान्य मूल्य पर आवेदक द्वारा सूचना प्रदान की जाती है, तो विधि का कोई उल्लंघन नहीं है।
- (3) निम्नलिखित कारणों से चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए:-
 - (क) चीन के प्रतिवादी निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वे ये सिद्ध नहीं कर देते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।
 - (ख) ऐसी परिस्थितियों में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को खारिज कर दिया जाना चाहिए जिनमें चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों (आईएस) के अनुरूप की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता, वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित राजस्व और व्यय, परिसम्पतियों और देयताओं की परिशुद्धता और पर्याप्तता सुनिश्चित करती है।
 - (ग) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में जांच पर खरे नहीं उतरते हैं। इसके विपरीत आर्थिक क्षति की जांच करते समय ऐसी क्षति को सिद्ध करने के लिए एकल मापदंड की मौजूदगी को पर्याप्त माना जाता है। अन्य शब्दों में यदि एक मापदंड क्षति के विद्यमान होने के लिए पर्याप्त होता है, तो एकल मापदंड की विफलता, बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को खारिज करने के लिए पर्याप्त है।
 - (घ) यह सिद्ध करने का दायित्व प्राधिकारी का नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण में प्रचालन कर रही हैं और वह बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की हकदार हैं। इसके विपरीत यह सिद्ध करना चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का दायित्व है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं।
 - (ङ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप में इसका दावा नहीं करते हैं। यदि उक्त समूह के भाग स्वरूप एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- (4) यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामले में चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, परन्तु 8 (2) का आह्वान किए बिना केवल पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।
- (5) घरेलू उद्योग चीन में घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था और न ही वह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध थी। इसलिए आवेदक ने केवल जांच शुरू करवाने के प्रयोजनार्थ डीजीएडी की पद्धति के अनुसार संरक्षण के सिद्धांतों का अनुपालन करने के बाद चीन के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया था।

- (6) अनुच्छेद 5.2 (3) में किसी अनुक्रमण के विद्यमान होने के बारे में निर्यातक का निवेदन पूर्णतया गलत है और यह कानूनी रूप से निराधार है कि अन्य विधियों का इस्तेमाल करने के बाद ही संरचित मूल्य की विधि को प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 5.2 में तीन भिन्न विधियाँ उल्लिखित हैं और उनमें कोई समानता नहीं है अथवा उसमें किसी अनुक्रमण का कोई सुझाव निहित नहीं है। उक्त अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि आवेदक द्वारा “उपयुक्त” परिस्थितियों में तीन विधियों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 5.2 के अंतर्गत आवेदक का दायित्व वस्तुतः “उत्पाद का संरचित मूल्य” प्रदान करने तक सीमित है, जो कि जरूरी नहीं है कि वह मूल देश में अनिवार्य रूप से हो सकता है। इसके अतिरिक्त दायित्व मात्र “उत्पाद का संरचित मूल्य” प्रदान करने का है और न कि “उत्पाद का संरचित सामान्य मूल्य” प्रदान करने का।
- (7) इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में तृतीय देश से आयात कीमत, (ख) भारत में बिक्री कीमत और (ग) भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकता है, जिसके लिए विधिवत् समायोजन किया जाए जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ शामिल हों। यह भी निवेदन किया जाता है कि चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया “किसी अन्य आधार” पर विचार नहीं करें क्योंकि ऐसा लागू करना तभी आवश्यक होता है, जब विधि के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए अन्य आधार को लागू नहीं किया जा सकता है।
- (8) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किए गए निवेदनों को खारिज कर दें क्योंकि उनके उत्तर प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार पूरे नहीं हैं। प्रतिवादी पक्षकारों की आपूर्ति श्रृंखला पूरी नहीं है। चीन से प्रतिवादी उत्पादकों नामतः अमीनो-केम (एचके) कंपनी लिमिटेड और झेझियांग होंगशेंग ने अपनी पूरी मूल्य श्रृंखला की सूचना प्रदान नहीं की है क्योंकि चीन में उनके संबंधित प्रयोज्यताओं ने जांच में भाग नहीं लिया है। इन दोनों कंपनियों ने शंघाई अमीनो-केम कंपनी लिमिटेड और झेझियांग अमीनो-केम कंपनी लिमिटेड से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन सभी चार कंपनियों नामतः अमीनो-केम (एचके) कंपनी लिमिटेड, झेझियांग होंगशेंग, शंघाई अमीनो-केम कंपनी लिमिटेड और झेझियांग अमीनो-केम कंपनी लिमिटेड उसी “अमीनो-केम” समूह की सहायक कंपनियां हैं और ये संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात कर रही हैं। प्राधिकारी का ध्यान एआरडब्ल्यू, यूएसबी और एफएसपी के मामले की हाल ही की जांच की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की सूचना नहीं होने के कारण निर्यातकों के पूरे उत्तर को खारिज कर दिया था, जिनका जांच अवधि में भारत को निर्यात किए जाने का दावा किया गया था।
- (9) निर्यातकों ने बदनीयत से जांच में अडचन डालने के इरादे से जानबूझ कर प्राधिकारी से ऐसी सूचना को दबा कर रखा है।
- (10) उद्योग के पास उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर विधिवत् समायोजन करने के बाद आयात के आंकड़ों से उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत संरचित की गई है।

प्रतिवादी पक्षकारों के विचार

26. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) चीन जनवादी गणराज्य के लिए आवेदन-पत्र में परिकलित सामान्य मूल्य, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं का उल्लंघन है। जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के पैरा 10 के साथ-साथ आवेदन-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन, विधिवत् समायोजन करने के बाद उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है।
- (2) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य, अनुच्छेद 5.2 (3) के साथ पठित अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित अनुसार अनुक्रमण के आधार पर होना चाहिए, मात्र यह उल्लेख करते हुए कि वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।
- (3) याचिकादाता ने जापान जैसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विधि के अंतर्गत निर्धारित कार्यप्रणाली की घोर अनदेखी की है और जापान के लिए सामान्य मूल्य की संरचना, “उपयुक्त लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजित करने के बाद समान उत्पाद के लिए भारत में अदा की गई अथवा देय कीमत” के आधार पर की है।

- (4) जापान से निर्यातकों का निवेदन है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए अपने निजी निर्यातों के लिए मूल्य श्रृंखला का पूर्णतया प्रदर्शन किया है, जिसका सत्यापन भी इस उत्तर के प्रस्तुत करने से पहले कर दिया गया है।
- (5) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इसकी ओर ध्यान दिए बिना कि क्या चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए, इस जांच के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय “प्रतिनिधि देश” की कार्य प्रणाली को प्रयुक्त नहीं करें, चूंकि ऐसी पद्धति 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली है। चीन को उसी तरह से माना जाए जैसा कि पाटन-रोधी जांच के प्रयोजनार्थ विश्व व्यापार संगठन के किसी अन्य सदस्य को माना जाता है।
- (6) 11 दिसंबर, 2016 के बाद कोई भी सदस्य देश, चीन से आयातों पर कार्रवाई करते समय पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2 में शामिल किए गए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने पर मानक नियमावली का उपेक्षा नहीं कर सकेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त तारीख के बाद भारतीय मूल पाटन-रोधी विनियम ऐसा कोई भी प्रावधान को शामिल नहीं कर सकते हैं, जिससे चीन से निर्यात करने वाले उत्पादकों के लिए उनकी घरेलू कीमतों और लागतों से भिन्न अन्य आधार पर सामान्य मूल्य की स्थापना की स्वीकृति दी जा सके। इस प्रकार नयाचार की समाप्ति के बाद भारत को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का प्रयोग करके चीन के उत्पादकों के सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के करार के अंतर्गत कोई कानूनी आधार नहीं होगा, चूंकि गॉट, 1994 के अनुच्छेद 6 के क्रियान्वयन के करार और अन्य शामिल करार की आवश्यकताओं के अनुसार यह असंगत होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. जांच शुरू करने के चरण में प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने की पूर्वधारणा से जांच की कार्रवाई शुरू की थी। जांच शुरू करते समय प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी थी कि वे जांच शुरू करने की सूचना का उत्तर दें और वे बाजार अर्थव्यवस्था के अपने दर्जे का निर्धारण करने के लिए संबद्ध सूचना प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की पूर्वधारणा का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। साथ ही प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी अनुरोध कि था कि वह अपने देश में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दे कि वे संबद्ध सूचना प्रस्तुत करें।

I. चीन जनवादी गणराज्य

28. चीन से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए:

1. मैसर्स झिजियांग होंगशेंग
2. मैसर्स आमीनों केम (एसके) कं. लि.

29. पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- i. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गणतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संके.ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं ;
- ii. इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमयजार वा-म से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैरपार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यव्या-वाली प्रणाली से हुईवस्थाअर्थव्यमहत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;

iii. इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यक्षीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

iv. विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है।

30. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि किसी भी चीनी उत्पादकों में से किसी भी उत्पादक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) की शर्तों में बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए दावा नहीं किया है। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था कि वह एक उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, भली-भांति समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या अदायगी योग्य कीमत के आधार पर अनुमानित सामान्य मूल्य का निर्धारण करे।

31. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत में चीन ज.ग. से आयातित संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य को उत्पादन की लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और युक्तिसंगत लाभ मार्जिन के लिए तर्कसंगत परिवर्धनों के पश्चात “किसी अन्य आधार” पर निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तरों पर प्रमुख कच्ची सामग्रियों, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि के लिए अंतराष्ट्रीय कीमतों, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्रियों के उपयोग पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बिक्री की लागत के 5% की दर पर तर्क संगत लाभ भी जोड़ा गया है।

i. मैसर्स झिजियांग हांगशेंग और मैसर्स अमीनो कैम एचके में निर्यात कीमत

32. पीओआई के दौरान, झिजियांग हांगशेंग भारत को सीधे ही और उनके संबंधित पक्षकार मैसर्स अमीनों कैम-एचके के जरिए संबद्ध वस्तुएं निर्यात करता है जैसा कि प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 2 में उल्लिखित विवरण में दर्शाया गया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा, विदेशी माल भाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और अनिवार्य सत्यापन के बाद इसे स्वीकार किया गया

ii. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

33. चीन से अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए, जिन्होंने इस जांच में भाग लिया / सहभागित नहीं किया है, प्राधिकरण ने एंटीडिंग नियमों के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित किया है।

उत्पादक	निर्यातक	निर्धारित सामान्य मूल्य		निबल एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत	
		अमरीकी डालर/मी.टन	भारतीय रु./मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	भारतीय रु./मी.टन
झिजियांग हांगशेंग केमिकल कंपनी लि.	झिजियांग हांगशेंग / अमीनों कैम (एचके) कंपनी लि.	***	***	***	***
कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***

II. जापान

34. एक अन्य उत्पादक अर्थात् मैसर्स सुमितोमो केमिकल कं. लि. ने अपने असंबंधित/असंबद्ध निर्यातकों से प्राप्त उत्तरों सहित अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मैसर्स ईस्ट वेस्ट कार्पोरेशन
2. मैसर्स सुमिका केमटेक्स कं. लि.
3. मैसर्स बी आर केमिकल्स
4. मैसर्स ईनाबाटा एंड कं. लि.

i. मैसर्स सुमितोमो केमिकल्स कंपनी लि. के मामले में सामान्य मूल्य

35. उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली उत्तर की जांच की गई है और संभव सीमा तक सत्यापन किया गया है। मैसर्स सुमितोमो केमिकल्स कंपनी लि. ने घरेलू बाजार में अधिकतर संबद्ध वस्तुओं की सीधे ही बिक्री की है। व्यापार की सामान्य अवधि में संबंधित व्यापारियों अर्थात् मैसर्स इनावाता एंड कं.लि. और मैसर्स सुमिका केमटेक्स कं. लि. के जरिए घरेलू बाजार में सीमित मात्रा में भी बिक्री की गई थी। उत्पादक ने अपने उत्तर के परिशिष्टों में इसका विवरण उपलब्ध कराया है। बिक्री का लाभप्रदता परीक्षण किया गया और यह नोट किया गया कि कुल घरेलू बिक्री का 80% से कम सौदे लाभ प्रदान करने वाले हैं, इसलिए प्राधिकारी ने केवल लाभ प्रदान करने वाले बिक्री डेटा पर आधारित सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। निर्यातक के सामान्य मूल्य को नीचे दी गई सारणी में उल्लेख किए गए अनुसार निर्धारित किया गया है।

ii. मैसर्स सुमितोमो केमिकल्स कं.लि. के मामले में निर्यात कीमत

36. उत्पादक ने दो चैनलों अर्थात् भारतीय उपभोक्ता को सीधे ही साथ ही असंबंधित निर्यातकों के जरिए भी भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यात सीआईएफ शर्तों पर किए गए थे और उत्पादकों - निर्यातकों द्वारा उनके सीधे निर्यात के लिए दावा किए गए समायोजन अंतर्देशीय माल भाड़ा, विदेशी माल भाड़ा, बीमा लागत, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों और अन्य प्रयोज्य व्ययों के कारण हैं। इनका सत्यापन किया गया है और सही पाए जाने की सीमा तक स्वीकार किया गया है। सीधे निर्यातों के लिए निर्यातक की निवल निर्यात कीमत नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित की गई है।

iii. मैसर्स बी आर केमिकल्स एंड मैसर्स ईस्ट वेस्ट कार्पोरेशन के मामले में निर्यात कीमत

37. पी ओ आई के दौरान, मैसर्स बी आर केमिकल्स ने मैसर्स ईस्ट वेस्ट कार्पोरेशन के जरिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है जिन्हें मैसर्स सुमितोमो केमिकल्स लि. से अधिप्राप्त किया गया था। उक्त निर्यातों के विवरण उपर्युक्त व्यापारी/निर्यातकों में से प्रत्येक के द्वारा स्वतंत्र रूप से परिशिष्ट 2 में प्रस्तुत किए गए हैं। निर्यात सी आई एफ शर्तों पर किए गए थे और इन निर्यातों के लिए व्यापारी/निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजन अंतर्देशीय माल भाड़ा, विदेशी माल भाड़ा, बीमा लागत, बैंक प्रभारों, क्रेडिट लागत, कमीशन, एस जी एंड ए, लाभ और अन्य प्रयोज्य व्ययों के कारण हैं। तथापि, उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं इसलिए प्राधिकारी ने उत्पादक से निर्यातक को बताई गई बिक्री कीमत को स्वीकार किया है और प्रयोज्य समायोजनों के लिए इसका सत्यापन किया है। निर्यातक के लिए निर्यात कीमत को नीचे दी गई सारणी में उल्लेख किए गए अनुसार निर्धारित किया गया है।

अन्य असहयोगी निर्यातक

38. जापान से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्होंने इस जांच में भाग नहीं लिया/सहयोग नहीं किया है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) शर्तों में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दी गई सारणी में यथा उल्लेखानुसार निर्धारित किए गए हैं।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य		निवल निर्यात कीमत	
		अमरीकी डालर/मी.टन	भारतीय रु./मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	भारतीय रु./मी.टन
सुमितोमो केमिकल्स कं.लि.	सुमितोमो केमिकल्स कं.लि. / बी आर केमिकल्स एंड ईस्ट वेस्ट कार्पोरेशन	***	***	***	***
कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***

III. पाटन मार्जिन

39. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन संबद्ध वस्तुओं के एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निर्मित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत की तुलना के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नीचे दी गई सारणी सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन मूल्यों को दर्शाती है।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य		निवल निर्यात कीमत		पाटन मार्जिन			
		अमरीकी डालर / कि.ग्रा.	भारतीय रु. / कि.ग्रा.	अमरीकी डालर / कि.ग्रा.	भारतीय रु. / कि.ग्रा.	अमरीकी डालर / कि.ग्रा.	भारतीय रु. / कि.ग्रा.	%	रेंज
चीन									
झिजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लि.	झिजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लि/ अमीनो कैम (एचके) कं. लि.	***	***	***	***	***	***	***	40-50
कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	***	***	***	70-80
जापान									
सुमितोमो केमिकल्स कं.लि.	सुमितोमो केमिकल्स कं.लि. / बी आर केमिकल्स एंड ईस्ट वेस्ट कार्पोरेशन	***	***	***	***	***	***	***	15-25
कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	***	***	***	25-35

40. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों के लिए आयातों हेतु उक्त न्यूनतम स्तर से अधिक है।

छ. क्षति आकलन और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच के लिए कार्य प्रणाली

घरेलू उद्योग की राय

41. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए क्षति से संबंधित निवेदन नीचे दिए गए हैं :-

- पी ओ आई में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पिछले कुछ वर्षों की तुलना में विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने वृद्धि दर्शाई है। भारत में उत्पादन और उपभोग के संबंध में भी आयातों ने वृद्धि दर्शाई है;
- घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने रिकार्ड पर इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है कि कैसे घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटन के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण क्षति झेल रहा है। केवल अनिश्चिततापूर्ण बयान दिए गए हैं;
- मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा महत्वपूर्ण है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। यह संबद्ध देशों से उल्लेखनीय आयातों के कारण है;
- विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों के कमी किए जाने के साथ भारतीय उत्पादकों के पास केवल एक विकल्प बचा है, एक या तो वे आयात कीमतों में परिवर्तन के साथ अपनी कीमतों को पुनः गठित करें या आदेशों को खोए और परिणामतः बाजार हिस्से को भी खो दें;
- घरेलू उद्योग की कीमतें उन कीमतों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती हैं जो घरेलू बाजार में आयातकों द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
- कीमत से कम कीमत पर बिक्री और कीमत में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग कीमत ह्रास का सामना कर रहा है क्योंकि वे उचित शर्तों पर अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। इसका मुख्य कारण संबद्ध देशों से आयातों की उच्च मात्रा है वह भी पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर।

- vii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में महत्वपूर्ण सीमा तक लाभ, निवेशों पर वापसी और नकद लाभों के रूप में गहन रूप से ह्रास हुआ है।
- viii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट संबद्ध देशों से गैर-फायदेमंद कीमतों पर आयातकी मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण थी।
- ix. विरोधी पक्षकारों द्वारा यथा उल्लिखित क्षमता संबंधी आंकड़े गलत और आधारहीन हैं। ये संभवतः संयंत्र के लिए प्राप्त की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों से लिए गए आंकड़े प्रतीत होते हैं जो वास्तव में वास्तविक क्षमता या उत्पादन संबंधी आंकड़े नहीं हैं। जहां तक योजना के ह्रास का संबंध है, इन्हें प्राधिकारी द्वारा की गई संगणनाओं में विधिवत रूप से दर्ज किया गया है।
- x. बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में कम थी और इस प्रकार पाटित आयात घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास प्रभाव का सृजन कर रहे हैं।
- xi. घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के संबंध में महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहा है। परिकलित पाटन मार्जिन भी महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। इसके अतिरिक्त, यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो घरेलू उद्योग को लगातार क्षति के जोखिम की संभावना है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

42. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए क्षति से संबंधित निवेदन नीचे दिए गए हैं :-

- i. घरेलू उद्योग कथित पाटित आयातों से किसी महत्वपूर्ण क्षति का सामना नहीं कर रहा है, इसके विपरीत, पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। 2012-13 से 2013-14 तक, समान दर पर आयातों और घरेलू दोनों प्रकार की बिक्रियों में वृद्धि हुई है, इसलिए, आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में कोई सह-संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। याचिका के प्रोफार्मा IV क पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अधिकतर मानदंड क्षति अवधि में सुधार को प्रतिबिंबित करते हैं।
- ii. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, यह आत्म-प्रवृत्त है। घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त पुरानी और अकार्यकुशल प्रक्रिया के कारण है।
- iii. याचिकाकर्ता जान-बूझ कर बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करने में विफल रहा है जिनका संबद्ध देशों से आयातों से स्वतंत्र घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।
- iv. किसी प्रकार की कोई कीमत कटौती, कीमत दमन और ह्रास नहीं हुई है और इसलिए, संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की क्षति के दावे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- v. क्षति मार्जिन, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा परिकलित किया गया है, को उपलब्ध कराए अपर्याप्त डेटा/सूचना के कारण निर्यातकों द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता ने ए डी नियमावली के अनुबंध-II और अनुबंध-III में यथा निर्धारित की गई सभी शर्तों को पूरा किया है।
- vi. संयंत्र ने 2003 में उत्पादन आरंभ किया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई कानूनी याचिकाओं के अनुसार, उस समय की संस्थापित क्षमता 5520/मी.टन थी और जो उसके पश्चात लगातार उसी स्तर पर बनी रही। इसलिए संयंत्र की क्षमता (1) 5520 मी.टन है और (2) पूरी तरह से मूल्यहासित है तथा एन आई पी को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए।

- vii. यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता को ऐसी कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया गया है जो उसे क्षति अवधि की तुलना में परिवर्तित लागत का सामना करने की अनुमति नहीं देता। बिक्री कीमत में वृद्धि के साथ, याचिकाकर्ता ने क्षति अवधिकी तुलना में स्थिर लागतों का भी अनुभव किया है, जिसके द्वारा कीमतों में लागत की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- viii. याचिकाकर्ता का फोकस वृहत मांग-आपूर्ति अंतर के बावजूद निर्यातों के मामले में उच्च बिक्री आय के कारण घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बाजार पर अधिक रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के लिए निर्यात एक प्राथमिकता है और न कि एक विवशता।
- ix. उनका एक बिक्री चैनल है जो कि अत्यधिक अप्रतिस्पर्धात्मक भी है। वे अपने संवितरण नेटवर्क की लागत को बचाने के लिए कम कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं। कुछ बड़े ग्राहकों के अतिरिक्त उनके व्यापार का अधिकतम भाग ऐसे चैनलों के जरिए किया जाता है।
- x. कम होती हुई लाभप्रदता का याचिकाकर्ता की किसी भी कीमत या लागत मानदंडों के साथ कोई संबंध प्रतीत नहीं होता यदि याचिकाकर्ता की लाभप्रदता संबद्ध देशों से आयातों के कारण ऋणात्मक रूप से प्रभावित हो रही थी, तो पहुंच कीमतों में किसी भी प्रकार की वृद्धि याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में भी वृद्धि करती। यह तथ्य कि लाभों में ऐसी अवधि के दौरान वृद्धि होती है जब कथित पाटन (गिरती हुई आयात कीमतों) होने का आरोप लगाया गया है, भी कारण कार्य संबंध में अत्यधिक उल्लंघन का प्रमाण है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि लाभ/हानि के आंकड़ों में स्पष्ट प्रमाणिक वृद्धि है। यदि प्रति यूनिट लाभ/हानि नकारात्मक है तो, कुल लाभ/हानि सकारात्मक नहीं सकती।
- xi. आयातों में महत्वपूर्ण अंतर है जैसा कि याचिकाकर्ता और डी जी सी आई एंड एस द्वारा रिपोर्ट की गई है।
- xii. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने क्षमता संबंधी आंकड़ों को गलत रूप से प्रस्तुत किया है।
- xiii. नियोजित पूंजी में प्रबल रूप से गिरावट होने का कोई कारण नहीं है जबकि किए गए निवेशों की पूर्ण असंगति में, अगले वर्ष पूंजीगत निवेश किए गए और उनमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- xiv. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने क्षमता विस्तार में पूंजी निवेश किया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ संगत सरकारी प्राधिकारियों के पास उनकी कानूनी फाइलिंग में से किसी में भी ऐसे क्षमता विस्तार का कोई प्रमाण नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

43. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की ए डी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (IV) की शर्तों में जांच की जानी है। एतदधीन प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण, प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए और वर्तमान जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को संबोधित करते हैं। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 3 और डी जी ए डी की स्थापित पद्धतियों के अनुसार क्षतिरहित कीमत को अभिकलित किया है।

44. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्राधिकारी ने ऊपर दी गई नियमावली के अनुबंध II के अनुसरण में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, पाटन का परिमाण और मार्जिन जैसी उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है। चोट विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण ने डीजीसीआई और एस से प्राप्त आयात डाटा पर भरोसा किया है।

i. मांग का आकलन

45. इस प्रयोजन के लिए, भारत में विषय वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय निर्माता की घरेलू बिक्री (व्यापारी और साथ ही कैप्टिव) के रूप में लिया जाता है और सभी स्रोतों से आयात किया जाता है।

	विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	विषय देशों से आयात	मी.टन	2,470	2,889	3,226	3,343
2	अन्य देशों से आयात	मी.टन	372	425	92	177
3	भारत में घरेलू उद्योग की कुल बिक्री	मी.टन	1,095	1,557	886	1,169
i	व्यापारी बिक्री डी आई	मी.टन	965	1,100	674	953
ii	कैपिटल बिक्री डी आई	मी.टन	130	457	212	216
4	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	0	0	0	0
5	कुल मांग	मी.टन	3,937	4,871	4,204	4,689

46. प्राधिकरण का कहना है कि आधार वर्ष के मुकाबले भारत में कुल मांग पीओआई में बढ़ी है, यह ध्यान दिया जाता है कि 2013-14 के दौरान मांग में वृद्धि हुई थी, जिसका घरेलू बिक्री बढ़ने में भी अनुवाद किया गया है।

ii. पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

47. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से भारत में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष में। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एण्ड एस से अधिप्राप्त आयात डाटा का आश्रय लिया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
चीन से आयात (मी.टन)	549	1433	1030	1107
सूचीबद्ध	100	261	187	201
जापान से आयात (मी.टन)	1921	1456	2196	2236
सूचीबद्ध	100	76	114	116
संबद्ध देशों से आयात (मी.टन)	2470	2889	3226	3343
सूचीबद्ध	100	117	131	135
अन्य देशों से आयात (मी.टन)	372	425	92	177
कुल आयात(मी.टन)	2,842	3,314	3,318	3,519
आयातों में संबद्ध देशों का % हिस्सा	87%	87%	97%	95%
आयातों में अन्य देशों का % हिस्सा	13%	13%	3%	5%
संबद्ध देशों से आयातों में रुझान	100	116.94	130.57	135.31
घरेलू बिक्री	965.45	1,099.98	673.95	952.64
प्रवृत्ति	100	113.93	69.8	98.67
कुल मांग(मी.टन)	3,807.74	4,414.16	3,991.97	4,472.08
प्रवृत्ति	100	115.9	104.8	117.44
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	65%	65%	81%	75%
मांग में अन्य देशों का % हिस्सा	10%	10%	2%	4%

48. यह टिप्पणी की गई है कि संपूर्ण क्षति अवधि और पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में कुल रूप में लगातार वृद्धि हुई है। पी ओ आई के दौरान कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा लगभग 95% रहा है जो किसी भी मानक के अनुसार, जो भी हो, महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान चीन से आयातों की मात्रा दोगुनी हुई है और जापान से आयातों ने आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान 16% की वृद्धि दर्शाई है। संबद्ध देशों से कुल आयातों ने आधार वर्ष (2012-13) में 2470.28 मी.टन से पी ओ आई (2015-16) में 3342.73 मी.टन की वृद्धि दर्शाई है। मांग के संबंध में आयातों के हिस्से में पी ओ आई के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जब इसकी आधार वर्ष से तुलना की जाती है। तथापि, पिछले वर्ष से तुलना किए जाने पर इसमें गिरावट दिखाई देती है।

iii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

49. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अनिवार्य है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना करने पर कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अन्यथा रूप से ह्रास करता है या कीमत में वृद्धि को रोकता है, जो सामान्य अवधि में अन्यथा रूप से बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर होने वाले प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत से कम कीमत पर बिक्री और कीमत में दमन और कीमत में गिरावट, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की जाती है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री आय (एन एस आर) और गैर-क्षतिकारक कीमत (एन आई पी) की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच लागत से तुलना की गई है।

क) कीमत दमन और ह्रास

50. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का दमन या उनमें ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक उल्लेखनीय सीमा तक कीमतों का दमन करता है या कीमतों में वृद्धि को रोकता है, जो अन्यथा रूप से सामान्य अवधि में घटित हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार तुलना की गई थी:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./मी.टन	309,154	345,788	356,694	315,081
विक्रय मूल्य	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100.00	108.39	114.23	109.79
लागत प्रति यूनिट	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100.00	108.39	114.23	109.79

51. उपरोक्त से, यह ध्यान दिया जाता है कि कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण, वर्ष 2014-15 के दौरान वृद्धि के साथ बेस ईयर की तुलना में विषय वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में मामूली वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य के लिए, यह ध्यान दिया जाता है कि वही वृद्धि हुई है, लेकिन पूरी चोट अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि विषय आयात के उतराए गए मूल्य डीआई के बिक्री की लागत से कम है। यह घरेलू उद्योग के दावे की पुष्टि करता है कि वे हमेशा पंपों के आयात से कीमत के दबाव में हैं और अपने सबसे खराब बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए उन्हें सबसे कम आयात की कीमतों के साथ मिलना पड़ता है। यह नोट किया गया है कि पिछले वर्ष (2013-14 और 2014-15) की तुलना में विषय देशों से आयात का लैंडिड मान पीओआई के दौरान घट गया। पूर्वोक्त से, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग मूल्य दमन / अवसाद का प्रभाव महसूस कर रहा है।

ख) कीमत में कटौती

52. घरेलू उद्योग ने कहा है कि वे विषय देशों के निर्यातकों से निरंतर दबाव में थे और अपने घरेलू बाजार हिस्सेदारी को बरकरार रखने के लिए आयात की सबसे कम कीमतों की बिक्री मूल्य कम रखा। डीजीसीआई और एस से प्राप्त आयातों की उगाए गए मूल्य की बिक्री की कीमत के साथ तुलना में नीचे की गई है और यह नोट किया जाता है कि कीमत का दबाव नकारात्मक है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./मी.टन	3,09,154	3,45,788	3,56,694	3,15,081
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	108	114	110
कीमत में कटौती	रु./मी.टन	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत में कटौती	%	(***)	(***)	(***)	(***)
रेंज	अनुक्रमित	(15)-(5)	(15)-(5)	(15)-(5)	(10)-(1)

ग) कीमत से कम कीमत पर बिक्री

53. प्राधिकरण ने विषय देशों द्वारा कथित रूप से आयात किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की गई कीमतों की जांच भी की है। विश्लेषण घरेलू उद्योग के एनआईपी और चीन और जापान के सहकारी निर्यातकों के आयात के उतरा हुआ मूल्य के आधार पर किया गया है, जो संबंधित विषय देशों से कुल आयात के लिए खाता है।

विवरण	यूनिट	चीन	जापान
एनआईपी	रु./मी.टन	***	***
आयात की पहुंच कीमत	रु./मी.टन	***	***
कीमत से कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.टन	***	***
कीमत से कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कीमत से कम कीमत पर बिक्री	रेंज	10-20	10-20

54. उपर्युक्त सारणी से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कीमत से कम कीमतों पर बिक्री का सामना कर रहा है।

iv. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

55. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II यह अपेक्षा करता है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों की उद्देश्यपूर्ण जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन और बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्से की उत्पादकता, निवेशों पर वापसी या क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिनकी मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावनी कृणात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों को शामिल करना चाहिए।

56. घरेलू उद्योग और विषय देश से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे विचार विमर्श किया गया है:

i. बाजार हिस्सा:

57. घरेलू उद्योग के आयातों, घरेलू बिक्रियों और बाजार हिस्से के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

SN	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	कुल घरेलू बिक्री (कैप्टिव बिक्री सहित)	MT	1,095	1,557	886	1,169
1a	विवरण	Indexed	100	142	81	107
2	संबद्ध देशों से आयात	MT	2,470	2,889	3,226	3,343
3	अन्य देशों से आयात	MT	372	425	92	177
4	कुल आयात	MT	2,842	3,314	3,318	3,519

5	कुल मांग	MT	3,937	4,871	4,204	4,689
5a	विवरण	Indexed	100	124	107	119
6	मांग में बाजार हिस्सा					
6a	घरेलू बिक्री का	%	28	32	21	25
6b	संबद्ध देशों से आयातों का	%	63	59	77	71
6c	अन्य देशों से आयातों का	%	9	9	2	4

58. यह देखा जाता है कि विषय देशों से विषय वस्तु का आयात पूरी चोट अवधि के दौरान लगातार बढ़ गया है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि आधारभूत वर्षों की तुलना में घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सेदारी पीओआई के दौरान मामूली कमी आई है जबकि विषय देशों से आयात का हिस्सा बढ़ गया है।

ii. लाभ प्रदत्ता:

59. याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूरी चोट की अवधि के दौरान उन्हें नुकसान हुआ है। बिक्री की कीमत में वृद्धि हुई है, हालांकि यह पूरी चोट की जांच की अवधि और पीओआई के दौरान लगातार बिक्री की लागत से कम रही है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	POI
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	109	102
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	108	114	110
लाभ/हानि	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	(135)	(81)	(136)

60. उपरोक्त से, यह ध्यान दिया जाता है कि कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण, वर्ष 2014-15 के दौरान वृद्धि के साथ आधार वर्ष की तुलना में विषय वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में मामूली वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य के लिए, यह ध्यान दिया जाता है कि वही वृद्धि हुई है, लेकिन पूरी चोट अवधि के दौरान बिक्री की लागत से नीचे है, इसलिए, डीआई पूरी अवधि के दौरान घाटे में पड़ रही है।

iii. निवेश पर वापसी :

61. पूर्ण क्षति अवधि के दौरान निवेशों पर वापसी में उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई
लाभ प्रति यूनिट	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	(100)	(83)	(91)	(78)
आर ओ सी ई	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	(100)	(116)	(48)	(61)

IV उत्पादन और क्षमता उपयोग:

62. घरेलू उद्योग ने 2013-14 के दौरान अपनी क्षमता में मामूली वृद्धि की है (मुख्य रूप से डेबोटलेनेक्कींग के कारण) और उसके बाद भी एक समान रहा। घरेलू उद्योग का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है जो काफी हद तक इस तथ्य की वजह से है कि देश में मांग बढ़ गई है। इसके अलावा, क्षमता का उपयोग, पूरी चोट अवधि के दौरान लगातार बढ़ गया है।

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई
क्षमता (मी.टन)	2160	2280	2280	2280
प्रवृत्ति	100	106	106	106
उत्पादन (मी.टन)	1,607	1,941	1,967	2,055
क्षमता उपयोग (मी.टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	114	116	121

V. बिक्री मात्रा :

63. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वर्ष 2013-14 में उच्चतम शिखर के साथ आधार वर्ष के मुकाबले पीओआई में मामूली वृद्धि और 2014-15 में गिरावट आई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि वे मांग में वृद्धि के बावजूद बिक्री की मात्रा में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुए हैं, जिससे उन्होंने इस तथ्य को सौंपा है कि विषय देशों के निर्यातकों ने डंपिंग तकनीक अपनाई है। उन्हें निर्यात करना पड़ा क्योंकि घरेलू बाजार में कीमतों की तुलना में निर्यात बाजार में बेहतर कीमतें मिल रही हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे घरेलू बाजार में लाभकारी कीमतों पर एक बड़ा हिस्सा पसंद करेंगे, खासकर भारत में मांग लगातार बढ़ रही है।

SN	विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	घरेलू बिक्री (व्यापारी बिक्री)	मी.टन	965	1100	674	953
1a	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	70	99
1a	बिक्री मूल्य - घरेलू	रु./ मी.टन	***	***	***	***
1b	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	110
2	कैप्टिव बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
2a	बिक्री मूल्य- कैप्टिव	रु./ मी.टन	***	***	***	***
2b	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	102	101
3	निर्यात बिक्री	मी.टन	455	420	1088	815
3a	बिक्री मूल्य - निर्यात	रु./ मी.टन	***	***	***	***
3b	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	108	114

64. यह ध्यान दिया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में निर्यात की बिक्री पीओआई के दौरान लगभग दोगुनी हो गई है और घरेलू बिक्री के मुकाबले यह बेहतर प्रतिलाभ कीमत पर है। यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि घरेलू उद्योग कुशल है और विषय वस्तु समान गुणवत्ता वाले हैं जो उन्हें निर्यात बाजार बनाने और अच्छे दामों को महसूस करने के लिए सक्षम करते हैं। इसके अलावा यह नोट किया गया है कि उनकी घरेलू बिक्री (व्यापारी और कैप्टिव) डीई की कुल बिक्री का लगभग 60% है, हालांकि भारत में व्यापारी बिक्री की बिक्री मूल्य निर्यात मूल्यों से कम है और कीमतें जिन पर विषय वस्तुएं चल रही हैं कैप्टिव सेवन किया गया (उत्पादन शुल्क की लागत कम होने पर प्रशासनिक खर्च - लागू हस्तांतरण मूल्य कानूनों के अनुसार) हालांकि, वर्तमान चोट विश्लेषण केवल मर्चेट बिक्री के लिए दम आयात के कारण हुई चोट के आधार पर है।

vi. माल सूची :

65. यह नोट किया गया है कि आदर्श परिस्थिति में घरेलू उद्योग की औसत सूची 4-5 दिनों के लिए है लेकिन यह पीओआई में वृद्धि के साथ उच्चतर तरफ है।

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई
औसत स्टॉक (मी.टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	133	55	167

vii. उत्पादकता, रोजगार और वेतन:

66. सारणी से यह देखा गया है कि पी ओ आई के दौरान कर्मचारियों की संख्या उसी स्तर पर बनी रही है जिस पर यह आधार वर्ष में थी। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह इस कारण है कि उन्हें पाटित आयातों द्वारा प्रस्तावित कीमतों से मेल करने के लिए अपनी लागतों को कम करना पड़ा है। तथापि, आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान उन्हें अदा की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है। रोजगार और मजदूरी के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई
उत्पादन (मी.टन)	1,607	1,941	1,967 2,055	1,607
प्रवृत्ति	100	121	122 128	100
कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	98	97	100
उत्पादन / कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	124	126	128
मजदूरी/ कर्मचारी (रु.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	106	99	110

67. मजदूरी में वृद्धि एक प्राकृतिक कारण है और कथित डंपिंग के कारण नहीं है। वास्तव में कर्मचारियों की संख्या एक ही है, जबकि उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह इंगित करता है कि वे अधिक कुशल बन गए हैं जो संख्या के अनुसार अधिक संकेत है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन बढ़ गया है।

viii. पाटन का परिमाण :

68. सामान्य निर्यात / सामान्य मूल्य की तुलना के साथ डंपिंग का परिमाण पूर्व निर्धारित कारखाने के स्तर पर उनके शुद्ध निर्यात मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और यह उस सीमा का एक संकेत है जिसके लिए आयातित आयात घरेलू उद्योग में चोट लग सकती है वर्तमान मामले में विषय देशों के खिलाफ निर्धारित डंपिंग मार्जिन न्यूनतम से ऊपर है।

ix. वृद्धि

69. घरेलू उद्योग की वृद्धि को सकारात्मक रूप में नहीं कहा जा सकता है विषय वस्तु के लिए मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद मुनाफे और आरओएसई पूरी चोट अवधि और पीओआई के दौरान नकारात्मक रहा। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग को मुनाफे में वृद्धि, नकदी प्रवाह को सुविधाजनक और निवेश पर बदले में वृद्धि की उम्मीद थी। हालाँकि, घरेलू उद्योग, विषय देशों से पंपों के आयात की उपस्थिति के कारण ही हासिल करने में सक्षम नहीं था, जैसा कि एक सकारात्मक अनुमान और सकारात्मक मूल्य दमन और अवसाद से स्पष्ट है।

x. घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

70. जांच संकेत करती है कि संबद्ध वस्तु के लिए भारत में लाभप्रद मांग है। संबद्ध देशों से पाटित आयात कीमतें घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही है। यह भी देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध

वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत/गैर-क्षतिकारक कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से पहुंच मूल्यों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन/ह्रास किया है जिस कारण उन्हें वित्तीय हानि हुई। संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से विचाराधीन उत्पादन के आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं या गैर-पाटित कीमतों पर बिक्री किए जा रहे हैं क्योंकि इन देशों द्वारा प्रस्तावित कीमतें उल्लेखनीय रूप से अधिक हैं और इसलिए यह घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही कीमत दमन और ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। अतः इसके विवेकपूर्ण प्रमाण है कि संबद्ध देशों से पाटित वस्तुएं घरेलू उद्योग की दमित और ह्रासित कीमतों के लिए उत्तरदायी हैं।

V. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

71. महत्वपूर्ण क्षति विद्यमानता की जांच करते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा कीमत से कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास व दमन प्रभावों, भारतीय नियमावली और पाटन रोधी करार के तहत अन्य सांकेतिक मानदंडों की शर्तों में, घरेलू उद्योग की कीमतों, पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए जांच की गई है कि क्या कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति में अंशदान कर सकता है।

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

72. पी ओ आई के दौरान, संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा उल्लेखनीय नहीं है और वे उच्च कीमतों पर प्रस्तुत की गई थीं। इसलिए, अन्य देशों से आयात को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं समझा जा सकता।

(ख) मांग में संकुचन

73. पूर्ण अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है।

(ग) उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन:-

74. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उपभोग के पैटर्न में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए घरेलू द्वारा सामना की जा रही क्षति का कारण नहीं हो सकता।

(घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा:-

75. प्राधिकारियों ने टिप्पणी की है कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति में अंशदान कर सकती हैं।

(ड.) प्रौद्योगिकी में विकास:-

76. प्राधिकारी ने भी टिप्पणी की है कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारक नहीं है।

(च) निर्यात निष्पादन:

77. केवल उनके घरेलू प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण किया गया है। इसलिए, निर्यात बाजार में निष्पादन ने वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया है।

(छ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन:

78. घरेलू उद्योग का क्षति से संबंधित दावा केवल विचाराधीन उत्पाद के कारण है। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया है।

ज. क्षति और क्षति मार्जिन का परिभाषा

79. ए डी नियमावली के अनुबंध III की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की

क्षतिरहित कीमत की तुलना पी ओ आई के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार तैयार किया गया क्षति मार्जिन इस प्रकार है:

उत्पादक	निर्यातक	एन आई पी		पहुंच मूल्य		क्षति मार्जिन			
		अमरीकी डालर /मी.टन	भारतीय रु./मी.टन	अमरीकी डालर /मी.टन	भारतीय रु./मी.टन	अमरीकी डालर /मी.टन	भारतीय रु./मी.टन	%	रेंज
चीन									
झिजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लि.	झिजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लि./ अमीनो केमि. (एचके) कं.लि.	***	***	***	***	***	***	***	10-20
कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	***	***	***	35-45
जापान									
सुमितोमो केमिकल्स कं.लि.	सुमितोमो केमिकल्स कं.लि. / बी. आर. केमिकल्स कं. लि. एंड ईस्ट वेस्ट कापोरिशन	***	***	***	***	***	***	***	10-20
कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	***	***	***	25-35

प. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

80. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। उनमें उठाए गए मुद्दे जांच के दौरान पूर्व में पहले ही उठा दिए गए हैं और उनका समुचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है :

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

81. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां निर्धारित समय-सीमा के बाद कीं और इसीलिए उन पर विचार नहीं किया गया।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

82. विभिन्न विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:

- प्रकटन विवरण के संबंध में अनुरोध करने के लिए समयसीमा तर्कसंगत रूप से उचित रूप से उत्तर दिए जाने के लिए और हितों की रक्षा पर्याप्त रूप से करने के लिए बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 के अनुरूप नहीं है।
- एक जापानी कंपनी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों का घरेलू समान उत्पाद से कोई लेना-देना नहीं है। तर्क घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया की अपर्याप्तता के संबंध में किए गए थे, इस प्रकार एक स्व-प्रभावित क्षति हुई और कारणात्मक संबंध को तोड़ा गया। घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से अदक्ष होने के नाते उनकी लागत अनावश्यक रूप से अधिक होती है। जिससे स्वप्रभावित वास्तविक क्षति हुई है। इस तर्क का विचाराधीन

उत्पादके क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, परंतु इसके बजाए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (v) में उल्लिखित गैर-जिम्मेदार कारकों से है।

- iii. कैप्टिव रूप से प्रयुक्त किए जा रहे आयातों के कारण संयुक्त राज्य अमरीका को हटाना इसके कानूनी आधार से ही नहीं है बल्कि यह भेदभावपूर्ण भी है। अंतिम प्रयोग के लिए आयातित उत्पाद कैप्टिव प्रयोग के लिए है अथवा व्यापार के लिए। इस पर ध्यान न देते हुए जहां तक देश के लिए आयात हैं, वे देश के लिए 3 प्रतिशत से अधिक थे और उन्हें संबद्ध देश माना जाना चाहिए।
- iv. प्रोफेसर और याचिकाकर्ता ने उप-उत्पाद के रूप में याचिकाकर्ता की अंतिम डिस्टिलेशन प्रक्रिया से रिसोर्सिनोल टार ("रेसो-टार") के उत्पादन की पूर्णतः उपेक्षा की है। यह तथ्य कि प्रोफेसर ने याचिकाकर्ता की उत्पादन प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में रेसो-टार का उल्लेख नहीं किया है, रिसोर्सिनोल टार की उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में अपने विश्लेषण में कमी को उजागर करता है और इस प्रकार उसके संबंध में उनकी टिप्पणियां पूरी तरह से उपेक्षित की जानी चाहिए जो उप-उत्पाद याचिकाकर्ता की प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं, वे आसानी से वाणिज्यिक रूप से नहीं बेचे जा सकते।
- v. याचिकाकर्ता ने सुमीटोमो कैमिकल कंपनी लिमिटेड के विस्तार पर बंदी का आरोप लगाकर इंडस्पेक की बंदी के संबंध में अपने पत्र दिनांक 5 दिसंबर, 2017 द्वारा झूठे आरोप लगाने का प्रयास किया है। निर्यातकों ने पूर्व में कहा था कि मार्च, 2017 में इंडस्पेक ने वैश्विक प्रतिस्पर्धाकर्ताओं की तुलना में विनिर्माण प्रक्रिया में अदक्षताओं के कारण संयंत्र की बंदी घोषित की थी।
- vi. याचिकाकर्ताओं का यह अनुरोध कि आयात निचले उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कैप्टिव खपत हेतु प्रयुक्त किए जा रहे हैं, गलत है। उनके द्वारा 2013-14 के दौरान जापान से आयात किए गए हैं और बाद में अन्य देश से किए गए थे ताकि वे अपनी आपूर्ति का अंतराल पूरा कर सकें क्योंकि उनके साथ 1,3 साइक्लोहेक्सानेडोइन, रेसोफॉम पी-18, रेसोफॉम पी-19 और रेसोफॉम पी-20 में उत्पाद करने की क्षमता नहीं है जिनके लिए कच्ची सामग्री के रूप में रिसोर्सिनोल की आवश्यकता होती है।
- vii. कारणात्मक संपर्क का अभाव है क्योंकि घरेलू उत्पादक की अदक्षता यह सिद्ध नहीं करती कि घरेलू उत्पादों की कीमत आयातित उत्पादों के पाटन के कारण मजबूरन कम हुई थी। घरेलू उद्योग की उत्पादन राशि तथा क्षमता उपयोग और उत्पादकता जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है। घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं है बल्कि उसकी अपनी प्रौद्योगिकीय अदक्षताओं और अन्य आवश्यक मुद्दों के कारण है।
- viii. प्रति इकाई लागत और प्रति इकाई बिक्री कीमत के लिए उसमें दिए गए आंकड़े (प्रवृत्ति) समान हैं।
- ix. याचिकाकर्ता की लागत उसकी अदक्ष उत्पादन प्रौद्योगिकी के कारण भारी मात्रा में बढ़ी है। इससे उत्पादन लागत अनावश्यक रूप से अधिक हुई है और परिणामस्वरूप बढ़ी हुई क्षति रहित कीमत बनी है। यदि एनआईपी अदक्ष प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ी है तो स्पष्ट रूप से विश्लेषण में कम बिक्री कीमत होगी।
- x. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध नहीं किया है कि आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं। वर्तमान जांच में संबद्ध देशों से नकारात्मक कटौती है। यदि कोई बाजार कीमत सापेक्ष है, जैसा कि याचिकाकर्ता के दावे से प्रतीत होता है, न्यूनतम कीमत बाजार में कीमत की प्रवृत्तियां निर्धारित करती है। वर्तमान मामले में कीमत प्रवृत्तियां याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित की जा रही हैं जिससे कीमत न्यूनीकरण अथवा यहां तक कि कीमत क्षति का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।
- xi. याचिकाकर्ता द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन असंगत हैं और वह याचिकाकर्ता की तथाकथित अपनी लागत पर विश्वास कर रहा है जिसका विचाराधीन उत्पाद के वैश्विक मानदंड से अत्यधिक विचलन होने का अनुमान है।
- xii. प्राधिकारी ने संचयी मूल्यांकन के लिए कोई आधार नहीं दिए हैं।

- xiii. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग उत्पादन और क्षमता से अधिक है। आयात मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए आ रहे हैं।
- xiv. प्राधिकारी ने मै. सुमिटोमो कैमिकल कंपनी लिमिटेड के सामान्य मूल्य के परिकलन के प्रयोजन के लिए लाभप्रद बिक्री पर भी विचार किया है क्योंकि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि मै. सुमिटोमो कैमिकल कंपनी लिमिटेड घरेलू बाजार में अपनी कुल बिक्री का **80%** से अधिक लाभप्रद बनाने में विफल रहा वस्तुतः घरेलू बाजार में **80%** से अधिक बिक्री लाभप्रद थी। प्राधिकारी ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उन्होंने अन्य गैर-लाभप्रद लेनदेनों की उपेक्षा क्यों की है।
- xv. प्राधिकारी ने इसे विस्तारपूर्वक नहीं बताया है कि उसमें लगाई गई **22%** पूंजी पर उपयुक्त आय के परिकलन के लिए **22%** कैसे हासिल किया। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उन मानदंडों को बताएं जो उन्होंने **22%** पर पहुंचने के लिए विचार में लिए हैं।
- xvi. प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध है कि वे उस स्थिति में पाटनरोधी शुल्क की के संदर्भ कीमत प्रारूप की सिफारिश करें जब सकारात्मक क्षति मार्जिन, सकारात्मक पाटन मार्जिन और कारणात्मक संपर्क सिद्ध हो। विश्व में रिसोर्सिनोल के लिए केवल तीन ही उत्पादक हैं जो भारत में सीमित आपूर्ति करते हैं जिससे उत्पाद प्राप्त करने के लिए आयातकों एवं प्रयोक्ताओं के लिए कठिनाई हो जाती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 83.** यह नोट किया जाता है कि प्रकटन पश्चात स्तर पर उठाए गए मुद्दों की उपर्युक्त संगत पैराग्राफों में प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच कर ली गई है, तथापि, अनुरोधों की स्पष्टता के लिए उनका निम्नलिखित रूप में समाधान किया जाता है
- i. जहां तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के अनुरोधों के लिए समयसीमा का संबंध है, सभी हितबद्ध पक्षकारों को 7 दिन का उपयुक्त समय दिया गया था। उत्तर देने के लिए समय पर्याप्त है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को केवल विसंगतियों अथवा गायब आंकड़ों/सूचना/अनुरोधों, यदि कोई हो, का भी उल्लेख करने की आवश्यकता है। निर्धारित समयावधि के अंतर्गत पर्याप्त टिप्पणियों का विधिवत रूप से समाधान कर दिया गया है।
 - ii. जहां तक कीमत प्रभाव विश्लेषण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम-16 के तहत प्रकटन विवरण का प्रयोजन विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से सभी पक्षकारों को सूचित करना है। प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के तहत प्रकटन के स्तर पर उसके निर्धारण को प्रकट करना अनिवार्य नहीं है। यह अंतिम चरण से पहले की स्थिति नहीं है और प्रकटन विवरण का प्रयोजन यह है कि सभी पक्षकार यह जान जाएं कि अनिवार्य तथ्य, सूचना/आंकड़े प्राधिकारी के समक्ष क्या-क्या हैं जो विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और प्रकटन विवरण जारी करने के चरण तक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए हैं जो अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण के लिए प्राधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए आधार बनाएं। यदि प्रकटन विवरण की विषयवस्तु से कोई हितबद्ध पक्षकार यह सोचता है कि जांच से संबंधित कोई तथ्य/सूचना/आंकड़े महत्वपूर्ण/संगत हैं और वे छूट गए हैं अथवा गायब हुए हैं अथवा प्राधिकारी द्वारा उन पर समुचित रूप से विचार किया गया है तो हितबद्ध पक्षकार उन्हें अंतिम जांच परिणाम में अपना अंतिम मत बनाते समय औचित्य के आधार पर विचार के लिए वे प्राधिकारी की जानकारी में ला सकते हैं।
 - iii. जहां तक एनआईपी के परिकलन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी और उत्पादन लागत का निर्धारण निदेशालय में अपनाई गई परिपाटियों तथा नियमों के अनुसार किया गया है। जापान में निर्यातक के लिए परिकलित उत्पादन लागत उनके लिए बहुत ही कम थी साथ ही निर्यातक के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था।
 - iv. घरेलू उद्योग की अदक्ष प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्यातक के आरोप की पुनः जांच की गई और यह पाया गया कि उनका अनुरोध सही नहीं है क्योंकि निर्यातक द्वारा दावा किया गया उप-उत्पाद बहुत कम मात्रा में (केवल 3 प्रतिशत तक) उत्पादित किया जाता है और उसकी बिक्री पहले ही एनआईपी में समुचित रूप से हिसाब में ले ली गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी अदक्ष नहीं है और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद के लिए तर्क की सुसंगतता एवं उस आधार पर कारणात्मक संपर्क आधारहीन है।

- v. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच से प्रकट हुआ कि वे कच्ची सामग्री के रूप में रिसोर्सिनोल का इस्तेमाल करके निचले स्तर के उत्पादों का विनिर्माण कर रहे हैं जोकि संबद्ध सामानों की उनकी अपनी कैप्टिव खपत द्वारा भी सिद्ध है।
- vi. जापान के लिए सामान्य मूल्य सहयोगी निर्यातक द्वारा दी गई विस्तृत सूचना के अनुसार निर्धारित किया गया है जबकि चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया गया है तथा इसके कारण उपर्युक्त पैराओं में विस्तार से दिए गए हैं।
- vii. मै. सुमिटोमो द्वारा दी गई सूचना की विधिवत रूप से जांच की गई और यथासंभव सीमा तक उसका सत्यापन किया गया एवं उत्पादन लागत नियमों के अनुसार निकाली गई। घरेलू बिक्री को 80/20 परीक्षण तक रखा गया और उसके बाद प्राधिकारी ने लाभप्रद बिक्री लेनदेनों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- viii. जहां तक संबद्ध देश के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका को चुनिन्दा रूप से अलग करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह संगत नहीं है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में एकल विनिर्माण सुविधा तब से बंद हो गई है जैसा कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया था।
- ix. बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के लिए प्रवृत्ति का उल्लेख करने वाली संख्याओं को ठीक कर दिया गया है क्योंकि यह एक टंकण की त्रुटि थी। तथापि, पूरे अंक सही थे और इसका जांच के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं है।
- x. चूंकि नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में उल्लिखित मानदंड वर्तमान मामले में लागू थे अतः क्षति विश्लेषण के लिए संचयी मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा सही-सही किया गया है।

त निष्कर्ष

84. उठाए गए मुद्दों की जांच करने और इच्छुक पार्टियों और तथ्यों द्वारा की गई प्रस्तुतियां इस शोध में दर्ज प्राधिकरण से पहले उपलब्ध कराई गई हैं, प्राधिकरण निष्कर्ष निकाला है कि:

में।

- i. विचाराधीन उत्पाद विषयगत देशों से अपने सामान्य मूल्य के नीचे भारत को निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग
- ii. विषय देश के विचाराधीन उत्पाद के डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग ने भौतिक चोट का सामना किया है।
- iii. सामग्री की चोट विषय देशों से पंप आयात के कारण हुई है।

ज इंडियन इंडस्ट्री के हित और अन्य मुद्दे

85. प्राधिकरण का कहना है कि आम तौर पर एंटी डंपिंग कर्तव्यों का उद्देश्य, घरेलू उद्योग में डंपिंग की अनुचित व्यापार पद्धतियों से होने वाली चोट को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके। देश के सामान्य हित में है यह माना जाता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों के मूल्य स्तर पर असर पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा एंटीडिंग उपायों से कम नहीं होगा, खासकर अगर घरेलू उद्योग के लिए चोट की निंदा करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की लेवी को आवश्यक राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। इसके विपरीत, एंटीडिंग उपायों को लगाने से डंपिंग प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को दूर किया जाएगा, घरेलू उद्योग में गिरावट को रोकने और विषय वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। एंटी डंपिंग उपायों का प्रभाव किसी भी तरह से विषय देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, और इसलिए, उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर असर नहीं होगा।

सिफारिश

86. प्राधिकरण का कहना है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था और डंपिंग, चोट और साझे लिंक के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी देने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। एंडी नियमों के संदर्भ में डंपिंग, चोट और साझे लिंक की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद

और ऐसी डंपिंग मार्जिन की स्थापना के साथ ही घरेलू उद्योग को भौतिक चोट के कारण इस तरह के आयात किए गए आयातों की वजह से प्राधिकरण का अनुमान लगाया गया है डंपिंग और चोट की भरपाई करने के लिए एंटीडिंग ड्यूटी की आवश्यकता होती है इसलिए प्राधिकरण यह मानता है कि विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित विरोधी डंपिंग ड्यूटी लगाने से तीन साल की अवधि के लिए केवल इसके अनुसार वर्णित तरीके और तरीके में ही जरूरी है

87. कम कर्तव्य नियम के संबंध में, प्राधिकरण डंपिंग और घाटे के मार्जिन के बराबर के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग में चोट को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, विषय वस्तुओं से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिश करता है।, विषय वस्तु के उतराए गए मूल्य और नीचे दिए गए तालिका के कल. 8 में वर्णित राशि के अंतर के रूप में, प्रदान किए गए मूल्य कल. 8 में दिए गए मूल्य से कम है। इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए आयात के लैंडेड वैल्यू सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा और उस अधिनियम के धारा 3, 3 ए, 8 बी, 9 और 9 ए के तहत शुल्क के अलावा सभी सीमाशुल्क में शामिल हैं।

ड्यूटी टेबल

क्र.सं.	टैरिफ मद*	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूओएम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29072100	"रेसोरसिनोल"	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झिजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लि.	झिजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लि./ अमीनो केमि. (एचके) कं.लि.	5461	मी.टन
2	29072100	"रेसोरसिनोल"	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कॉलम 1 के अलावा कोई भी संयोजन	कॉलम 1 के अलावा कोई भी संयोजन	5461	मी.टन
3	29072100	"रेसोरसिनोल"	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	5461	मी.टन
4	29072100	"रेसोरसिनोल"	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	5461	मी.टन
5	29072100	"रेसोरसिनोल"	जापान	जापान	सुमितोमो केमिकल्स कं.लि.	सुमितोमो केमिकल्स कं.लि.	5461	मी.टन
6	29072100	"रेसोरसिनोल"	जापान	जापान	कॉलम 4 के अलावा कोई भी संयोजन	कॉलम 4 के अलावा कोई भी संयोजन	5461	मी.टन
6	29072100	"रेसोरसिनोल"	जापान	कोई	कोई	कोई	5461	मी.टन
7	29072100	"रेसोरसिनोल"	कोई	जापान	कोई	कोई	5461	मी.टन

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

88. इस जांच परिणाम से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2018

(Final Findings)**Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Resorcinol originating in or exported from China PR and Japan.**

No. 14/37/2016-DGAD.—1. Whereas M/s. Atul Ltd. (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Resorcinol" (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from China PR and Japan (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No.14/37/2016-DGAD dated 13th October, 2016, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and Japan, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

- i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants, alleging dumping of Resorcinol originating in or exported from China PR and Japan
- ii. The Authority notified the Embassy of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- iii. The Authority issued a notification dated 13th October, 2016, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
- iv. The Embassy of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within prescribed time limit.
- v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-dumping Rules.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. M/s. Shanghai Amino-Chem Co., Ltd., China
 2. M/s. Sumitomo Chemical Co., Ltd, Japan
- vii. In response to the above notification, following exporters and producers have submitted exporter questionnaire responses.

1. M/s. Sumitomo Chemical Co., Ltd, Japan
 2. M/s. East West Corporation, Japan
 3. M/s. Sumika Chemtex Co. Ltd, Japan
 4. M/s. B R Chemicals Co. Ltd., Japan
 5. M/s. Inabata & Co. Ltd. , Japan
 6. M/s. Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd, China PR
 7. M/s. Amino Chem-(HK) Co., Ltd., HongKong
- viii. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. However, none of the responding producers/exporters from China have claimed MET.
- ix. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
1. M/s. Black Rose Industries Ltd., Mumbai
 2. M/s. Bhimrajka Impex , Mumbai
 3. M/s. Sheetal Chemicals , Hyderabad
 4. M/s. Singh Plasticizers & Resins (I) Pvt Ltd, New Delhi
 5. M/s. Techno Waxchem Pvt Ltd, Kolkata
 6. M/s. Rajsha Chemicals Pvt. Ltd, Vadodara
 7. M/s. Asiatic Colour-Chem Industries Limited, Ahmedabad
 8. M/s. Shodhana laboratories, Hyderabad
 9. M/s SRF Ltd, New Delhi
- x. The following importers/users have responded or submitted importers questionnaire responses:
1. M/s. Black Rose Industries Ltd., Mumbai
 2. M/s. Techno Waxchem Pvt Ltd, Kolkata
 3. M/s. Rajsha Chemicals Pvt. Ltd, Vadodara
 4. M/s. SRF Ltd, New Delhi
- xi. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of import of subject goods for the past three years, including the POI. The Authority has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation and the detailed information submitted by cooperative producers/exporters for computation and required analysis.
- xiii. The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;
- xiv. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters was conducted to the extent possible and considered necessary for the purpose of the investigation.
- xv. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production

and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

- xvi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
- xvii. Investigation was carried out for the period 1st April, 2015 to 31st March, 2016 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014- March 2015, and the POI.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 31st October, 2017. The parties, who presented their views in the oral hearings, were requested to file written submissions of their views expressed orally by 8th November, 2017, followed by rejoinder submissions by 15th November, 2017.
- xix. The last date for issue of Final finding was 12th October, 2017, however the same was extended for three months by Central Government in terms of Rule 17(1)(a) up to 12th January, 2018.
- xx. A Disclosure Statement was issued on 7.12.2017 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 14.12.2017 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxi. The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been addressed in this Final Finding.
- xxii. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperative.
- xxiii. *** in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$ = Rs. 65.91

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions by the Domestic Industry

4. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. According to the Domestic Industry, there is no difference in the subject goods produced by them and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods and have comparable manufacturing process and technology.
- ii. The petitioner is using sulfonation-fusion process. The production process of M/s Atul Ltd. is actually more efficient technically and commercially than the other producers participating in the investigation. To substantiate this, Domestic Industry had submitted a letter from Professor M. M. Sharma, from Institute of Chemical Technology, Mumbai, certifying that technology used by M/s. Atul Ltd. is most efficient and cost effective, as it is a integrated process and by-products are saleable at reasonable prices. The sulfonation is more stable and safe as compared to other process such as hydroperoxidation and MPDA hydrolysis. The other process namely hydroperoxidation is hazardous and a massive explosion had occurred in 2012 at Mitsui Chemicals which caused closure of their Resorcinol manufacturing plant since then. The MPDA-hydrolysis process is very expensive requiring high capital cost as well as it generates high quantity of effluent

making product costing very high. In any case, the arguments of the interested parties relating to the production process is devoid of any merit since the production process is not a relevant factor in Anti-Dumping Law. It is further stated that production process has never been considered as a determinative factor while identifying the PUC by the Authority in any of the earlier investigation.

Submissions made by the opposing interested parties

5. The submissions made by opposing interested parties are as follows:

- i. The production process used by the Domestic Industry and the Japanese producer is completely different. The fact that the DI's technology is different is a widely known fact and is widely published. All other plants in the world since the year 1914 have shut down that were using benzenedisulfonation technology to produce resorcinol as the technology is uneconomical.
- ii. Sumitomo's production process is hydroperoxidation, whose main raw materials are benzene and propylene. Acetone is a by-product that is produced in this process. On the other hand, the production process used by the Domestic Industry is benzenedisulfonation, whose main raw materials are benzene, caustic soda and oleum (sulfuric acid). The main by-products of this process are reso-tar, sodium2 sulphite and sodium sulphate. This difference in raw material yield leads to a difference in the cost of production between the benzenedisulfonation technology and hydroperoxidation technology. the Petitioner's process has a much lower yield than Exporters.
- iii. The Petitioner manufactures resorcinol via a benzenedisulfonation process which is not cost effective and causing injury to the petitioner since it continuously requires updates and maintenance, which is a substantial drain on the company's resources. This process is more than 100 years old, and being the oldest process in the industry, it entails the highest cost of production out of the various technologies and processes available for manufacturing resorcinol.
- iv. The petitioner uses sulfonation process for manufacturing Resorcinol. The process is costly and the by-products of Resorcinol cannot be easily commercially sold and it is all waste. Production via batch-process which is said to be used by the Petitioner requires more manpower juxtaposed to the manpower required to produce the subject goods using a fully automated continuous process and is much less efficient. It was further emphasised by their expert that the out dated technology of Domestic Industry is main reason for their injury and losses.
- v. Earlier the Designated Authority in the matter of anti-dumping investigation against imports of Copper Clad laminates held that the manufacturing process adopted by the domestic industry is outdated and expensive and due to a variety of extraneous reasons it has not been able to upgrade its manufacturing facilities. Non-absorption of developments in technology has been a major factor in the injury to the domestic industry. Authority concluded that there is absence of causal link between the dumping of the subject goods from subject countries and material injury to the domestic industry as the factors other than dumped imports have caused injury to the domestic industry.

Examination by the Authority

6. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Resorcinol". It is also known as Resorcin Meta-dihydroxy benzene, 1, 3 dihydroxy benzene or 1, 3 benzenediol. It is a crystalline, aromatic, hygroscopic, and white solid product that is water soluble and very conducive to derivatisation.
7. The subject goods are used in various industries like it is used as a adhesion promoter between the reinforcing material and rubber in the rubber industry, antiseptic agents in cosmetics preparations, specialized thermosetting wood-adhesive resins, starting material for a number of hydroxy benzophenone type ultraviolet stabilizers used in various plastic materials etc. The domestic industry has claimed that as per their market intelligence more than 60% of Resorcinol demand is in adhesive resins for rubber products, including tyres.
8. As regards the difference in the production process, the Authority examined the issue and noted that all the three manufacturing processes followed by the producers in Japan, China and India are resulting in the same products with same specification meeting the needs of the same consumers in the market place. Therefore, it is held that the distinction of production process is not relevant for the outcome of the

present investigation. Further, in the matter of Automotive Tyre Manufacturers Association V. DA, it was held by the Hon'ble CESTAT that:

“The submissions that imported goods are manufactured through a different process and that the imported goods differ in quality also do not invalidate the findings. Process of manufacture is not a relevant factor under anti-dumping law. Quality difference is also not material. The imported goods and domestically produced goods have the same use and have been correctly held to be ‘like article’ by the Designated Authority. In these facts and circumstances the submissions made in these appeals have no merit. The appeals fail and are rejected.”

9. The subject goods are classified under chapter heading 29072100. However, it has been claimed by the petitioner that the subject goods are also being imported under other tariff headings. Therefore, the Authority has decided that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances
10. The Authority notes from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.

B. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions by the Domestic Industry

11. The submissions made by the domestic industry are as follows:
 - i. The petitioner is the sole producer of the subject goods in India therefore the petitioner alone constitutes a major proportion of Indian production of the subject goods in terms of rules. The petitioner has sufficient standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.
 - ii. In relation to the issues of Domestic Industry having a related trader/exporter in China, it is stated that the related entity in China is not dealing in production/ exports of the subject goods. Therefore, the petitioner has not declared the fact as under the Rules also there is no such requirement to declare all entities if they are not involved in production / sales of subject goods.
 - iii. The petitioner has made imports from the subject country but prior to POI and later from non-subject country against duty free license for export production of 1-3-Cyclohexanedione (1,3-CHD), for which company is fully eligible to produce the said goods.
 - iv. Petitioner has not imported the subject goods from subject country during the POI. Petitioner is not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus the petitioner is eligible domestic industry under Rules 2(b) and 5(3) of the AD Rules.

Submissions made by the opposing interested parties

12. The submissions made by opposing interested parties are as follows:
 - i. The imports have been made by the Petitioner during the injury period. Petitioner has also imported the product under consideration merely two weeks after the period of investigation. This is clearly indicative of the behavioral pattern wherein the Petitioner continues to import the product under consideration to supplement its inconsistent supply in the domestic market.
 - ii. The Petitioner's imports (claimed to be for ‘captive consumption’) were clearly not for captive use since they had no environmental clearance to manufacture downstream products of resorcinol.
 - iii. The domestic industry has a related company in China namely Atul China Ltd. This company is a trading company and is involved in import-export. The petitioner has failed to disclose this fact to

the Authority at the beginning of the investigation and has given a false declaration in the petition that they are not related to any foreign entity or exporter.

Examination by the Authority

13. The application in the present case has been filed by M/s Atul Ltd., the only domestic producer of the product under consideration and who has provided detailed information for investigation in the matter of imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR and Japan. The Authority determined at the stage of initiation that the petitioner, the sole producer of the subject good, satisfy requirement of standing under the Rules and the Petitioner constituted domestic industry within the meaning of the Rules.
14. As regard the import being made by the Domestic Industry, the Authority notes the imports have been made from non-subject country. As for the capability and capacity to produce downstream products, the Domestic Industry has produced 1-3-CHD during POI which was duly verified from their books of accounts.
15. The production of the petitioner alone constitutes 100% of Indian production. Accordingly, after careful examination of the legal provisions and facts of the case, the Authority, therefore, determines that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

C. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

Submissions by the Domestic Industry

16. The submissions made by domestic industry are as follows:
 - i. The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
 - ii. The petitioner has provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.
 - iii. Information such as volume of exports to India, gross volume of sales in domestic market, production, sales, average price for exports to India have been provided in indexed version as the information is business proprietary information.
 - iv. None of the exporters has provided the non-confidential version which is an exact replica of their confidential version. They have kept all the volume related information confidential. They have also not provided any statement of claim of confidentiality. Further, the responses are in stark violation of the specific guidelines issued by the Designated Authority with regard to the procedure to be followed for filing of non-confidential version of the exporter's questionnaire responses. We would, therefore, request the Hon'ble Designated Authority to disregard the submissions of the interested parties and also to reject the response of exporters and deny them the individual treatment.

Submissions made by the opposing interested parties

17. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
 - i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to volume related information also.
 - ii. The petitioner has resorted to excessive confidentiality claim which has prevented interested parties from offering their comments. Capacity data is not clearly provided in the Petition, and there appears to be no reasonable justification provided to keep the same undisclosed. Non-confidential version of the petition is grossly inadequate. This is in direct violation to principles of natural justice. The petitioner has claimed excessive confidentiality with regard to following
 - a. Capacity, Capacity Utilization,

- b. International price of the raw material used for calculation of normal value,
 - c. Format A – raw material and packaging material consumption,
 - d. Format B- raw material consumption norm and comparison with actual consumption,
 - e. Format CI and CII- Statement of various expenses,
 - f. Format D- consumption and utilities,
 - g. Format E- Statement of sales realization
- iii. Capacity data is not clearly provided in the Petition, and there appears to be no reasonable justification provided to keep the same undisclosed. Such violation of the rules also contravenes Article 6.5 of the Anti-dumping Agreement, and should be immediately corrected.

Examination by the Authority

18. The Authority made available non confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
19. The various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority were examined. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.
20. The interested parties have raised arguments with regard to confidentiality of information. The Authority notes that the confidentiality claims of the interested parties are consistent with the practice being generally followed by the Authority. Wherever possible, the interested parties have provided non confidential version of the information. The domestic industry has provided indexed version of its various information contained in the confidential petition.

D. MISCELLANEOUS ISSUES

Submissions by the Domestic Industry

21. The submissions made by the domestic industry are as follows:
- i. The Authority should not accept responses of Chinese exporters as they have failed to discharge their obligation by providing correct and certified information. The responding producers from China have conveniently omitted to provide any information as to the subsidies received by them by the government of China which are amongst one of the major reason for low priced Chinese imports
 - ii. Technology used by Domestic Industry is very efficient. Further, they have submitted a letter to substantiate their point. Importers and exporters are only raising this issue to create bias in the mind of Authority.
 - iii. In relation to capacity expansion, it is submitted that these are long term decisions and taken in view of the demand in the country.
 - iv. Quality of subject goods of Domestic Industry is at par with any of the goods imported into India. Moreover, they are supplying to many customers and never anyone has raised any question about their reliability. In any case none of the parties concerned has fully substantiated their claim with evidences, therefore, the Authority should not accept these baseless claims.
 - v. The allegation that the plants has regular shutdowns is wrong and baseless.
 - vi. At the time of filing the application, the petitioner is only required to make his case based on the best information available to him, that can prima facie satisfy the Authority to initiate the

investigation. Post initiation, the Authority is free to collect and rely on the information given by DI, cooperative exporters or may collect it from any other reliable source. Further, under the rule 5(3), even the Authority is only required to prima facie satisfy itself for initiation of the investigation. In any case, petitioners had officially collected and used the import data for filing of the petition. The source of import data was also made available to all other interested parties and therefore, no prejudice can be caused to any interested party.

- vii. In relation to non-inclusion of USA in the subject countries, it is stated that the majority of the imports from USA are under advance license route for production of a different product namely 1,3 CHD which is exported. Therefore, ultimately these goods are not entering the main stream of commerce. Further, the company was already aware that the company in USA was about to close its operations due to environmental and other inherent issues and felt it appropriate not to include USA in the petition of anti-dumping investigation.

Submissions made by the opposing interested parties

22. The submissions made by the opposing interested parties are as follows:

- i. It would not be in public interest to impose anti-dumping duty to shield one inefficient domestic company which has not shown any interest in up-gradation of technology, to sell its products at higher prices in India.
- ii. There is no substantive evidence to prove the condition for initiation of the anti-dumping investigation, the Authority has not carried out the investigation appropriately and with enough scrutiny to the related facts. It is in short of legal and factual basis.
- iii. Domestic Industry is suffering injury due to out dated technology and therefore, their costing is too high.
- iv. The quality of goods produced by Domestic Industry is not good. Moreover, they are not reliable supplier. The Petitioner was not responsive to order requests due to which it had to start relying on imported stocks for regular supply of resorcinol. Petitioner was unable to obtain a reliable reputation in the market which resulted in the purchasers to look for alternative sources. It would not be in public interest to impose anti-dumping duty to shield one inefficient domestic company which has not shown any interest in up-gradation of technology, to sell its products at higher prices in India. The Authority should consider this aspect also while dealing this issue.
- v. The Domestic Industry based its examination relating to dumping margin and injury margin on the basis of imports data obtained from secondary source and therefore the initiation itself is on wrong premise.
- vi. USA is not made the subject country despite having more than 3% of the total imports. Petitioner has imported the subject goods from USA and the quantum of imports by petitioner from USA is quite significant. merchant sale of USA imports is less than 1.24% of the total imports in the country is entirely irrelevant, thus The meaning of merchant sales used by petitioner for attempting to exclude USA is quite misleading. The petitioner has strategically not added USA as the subject country. Otherwise the petitioner would have not been eligible under Rule 2(b) of AD Rules to file the present petition, moreover, the plant has shut down production only recently in the month of July, 2017, i.e., 291 (9.7 months) days after initiation of the present case. Considering the time that was taken by the Designated Authority in considering the petition and initiation of investigations
- vii. As Domestic Industry cannot fulfill the demand of Indian market, the imposition of anti-dumping duty would not be in the larger interest of downstream Indian Industries.
- viii. Resorcinol producers do not have intention of dumping nor they have used dumping as a method to increase exports to India.

Examination by the Authority

23. The specific submissions made by the opposing interested parties and considered relevant, are addressed by the Authority as below:

- i. As regards to the submission of the opposing interested parties concerning obsolete and polluting technology being used by the Indian industry, it is noted that the Domestic Industry is indeed using a different technology. However, they have necessary pollution clearances and have been producing subject goods for more than 10 years. In any case, none of the interested party has proved or provided any evidence to substantiate their claim that technology used by Domestic Industry is not cost effective. Further, merely because different parties are using different technologies, which maybe more or less effective, is not a reason for any party to indulge in dumping. In view of this, the Authority finds no merit in the claim of the opposing parties.
- ii. In relation to issues relating to quality, it is noted that the Domestic Industry is supplying subject goods to customers and their quality is acceptable to customers. It is also noted that they have a strong customer base in India, establishing that their goods are at par with the imported goods. In any case, none of the interested party has proved or provided any evidence to substantiate their claim that quality of Domestic Industry is not good or acceptable. Moreover, quality *per-se* is not an issue in the anti-dumping duty investigations.
- iii. Capacity expansion is a long term decision made on the overall demand and economics of the commodity. In any case any proposed capacity expansion has no bearing on the current facts and circumstances of the case.
- iv. As regards the public interest, the Authority notes that anti-dumping duty is to ensure fair trade and provide a level-playing field to the domestic industry. They are not a measure to restrict import or cause an unjustified increase in cost of products.
- v. In relation to the allegation of the Domestic Industry that Chinese Authority are giving subsidy to the producers / exporters of the subject goods, it is noted that the Domestic Industry has not substantiated their claim.
- vi. In relation to the non-inclusion of USA in the present investigation it is noted that this fact was examined by the Authority at the time of initiation of the investigation. The imports of subject goods from USA were approximately 4.5% of the total imports however, majority of it was imported by the petitioner against advance license for export production. As they were not meant for merchant sales in India, the same could not have contributed to dumping and related injury to the Domestic Industry.
- vii. As regards the allegation that initiation is on wrong premise, the Authority notes that the initiation is done on the basis of prima facie facts provided by the Domestic Industry. There is no law under the Anti-dumping that the analysis by the domestic industry in its application cannot be done on the basis of secondary sources data for example IBIS, Infodrive, etc., During the course of investigation, the Authority has called for transaction by transaction data from DGCI&S and analysis has been done on the basis of DGCI&S import data.

E. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

24. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers and exporters from the subject country filed the prescribed questionnaire responses.

- i. M/s Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd, China PR
- ii. M/s Amino Chem-(HK) Co., Ltd., HongKong
- iii. M/s Sumitomo Chemical Co., Ltd, Japan
- iv. M/s East West Corporation, Japan
- v. M/s Sumika Chemtex Co. Ltd, Japan
- vi. M/s B R Chemicals Co. Ltd, Japan
- vii. M/s Inabata & Co. Ltd. , Japan

Submissions by the Domestic Industry

25. The following are the submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. The Domestic Industry had filed full information with regard to the normal value and export price which was necessary for the purpose of initiation of an investigation. In terms of Rule 5, the Domestic Industry is required to give information which is sufficient to justify the initiation of an investigation. Necessary evidence had also been provided in support of their claim of normal value as well as export price.
- ii. There is no violation of law if the applicants provide information on constructed normal value based on the information reasonably available to them and after applying the principle of conservatism as per the consistent practice of the Designated Authority.
- iii. China PR should be treated as nonmarket economy country for the following reasons:
 - a) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
 - b) Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.
 - c) Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. Contrarily, while examining material injury existence of a single parameter is considered sufficient to establish such injury. In other words, where one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.
 - d) It is not for the Authority to establish that the responding companies are operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. But it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
 - e) Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
- iv. It has been submitted that the normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to Anti-dumping Rules without invoking proviso to 8(2) in view of the aforementioned facts and circumstances.
- v. The domestic industry was not in a position to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices in China nor were the same available in the public domain. The applicant, therefore, only for the purpose of initiation, constructed the normal value for China after following the principles of conservatism and as per the practice of the DGAD.
- vi. The submission of the exporter with regard to the existence of any hierarchy in Article 5.2 (iii) is completely flawed and that the constructed value method can be used only after the other methods are exhausted is legally unfounded. Article 5.2 provides for three different methods for there is no semblance or even suggestion of any hierarchy. All that the said Article states is that any of the three methods can be used in "appropriate" circumstances by the applicant. The obligation on the applicant under Article 5.2 is in fact limited to providing the "constructed value of the product" which may not necessarily be in the country of origin. Moreover, the obligation is simply to provide the "constructed value of the product" and not the "constructed normal value of the product".
- vii. The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) import price from third country into India, (b) selling price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. It is also submitted that since these options for determination of normal value are available, the Designated Authority may not

kindly consider "any other basis" because this is required to be applied only when other basis listed under the law cannot be applied.

- viii. The Authority is requested to kindly reject the submissions made by exporters/producers as their responses are not complete in accordance with the consistent practice of the Authority. Supply - Chain of Responding Parties not Complete, the responding producers from China namely Amino-chem (HK) Co. Ltd and Zhejiang Hongsheng have not provided their complete value chain as their related entities in China have not participated in the investigation. These two companies have not provided information relating to Shanghai Amino-Chem Co. Ltd., and Zhejiang Amino-Chem Co. Ltd. It is important to note that all the four companies i.e., Amino-Chem (HK) Co. Ltd., Zhejiang Hongsheng Co. Ltd., Shanghai Amino-Chem Co. Ltd., and Zhejiang Amino-Chem Co. Ltd. are the subsidiaries of same "Amino-Chem" Group and are involved in the production and trading of the subject good. Kind attention of the Authority is invited to the recent investigations of ARW, USB and FSP, wherein the Authority has rejected the complete response of exporters in the absence of complete value chain of production and sale of the subject goods claimed to have been exported to India during the POI.
- ix. The exporters had intentionally withheld the information from the Authority only with malafide intention to impede the investigation.
- x. The export price is constructed based on the information available from the import data after making due adjustment based on the best available information with the industry to make it comparable with normal value.

Submissions made by the opposing interested parties

26. The submissions made by the opposing interested parties are as follows:

- i. The normal value computed in the application for China PR is in contravention of the requirements as provided under Annexure I (7) of the AD Rules. Paragraph 10 of the Initiation Notification, as well as the Application, stipulates that the normal value for China PR has been computed on the basis of the cost of production, duly adjusted.
- ii. The normal value for China should be based on the hierarchy as mentioned in the Article 2.2, read with Article 5.2(iii) merely by stating that they could not provide any evidence.
- iii. The petitioner has blatantly disregarded the methodology stipulated under the law for normal value determination for a market economy country like Japan and constructed the normal value of Japan on the basis of "price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted, to include a reasonable profit margin".
- iv. Exporters from Japan submit that they have fully demonstrated the value chain for their own exports to India during the period of investigation, which has also been verified prior to the filing of this rejoinder.
- v. China must be treated in the same way as to any other WTO member for the purpose of anti-dumping investigation. The Authority is requested to not use "surrogate country" methodology in calculating normal value for this investigation regardless whether treating China as a market economy country, since such practice is bound to expire since 11th December, 2016.
- vi. After 11th December, 2016, any member country will no longer be able to derogate from the standard rules on the determination of the normal value included in Article 2 of the anti-dumping agreement while dealing with the imports from China. This clearly implies that after that date, the Indian basic anti-dumping regulations cannot contain any provisions allowing for the establishment of the normal value for the Chinese exporting producers on a basis other than their domestic prices and costs. Thus, India after the expiry of the protocol has no legal basis under the agreement of the WTO to calculate normal value of the Chinese producers using the non-market economy methodology, since it would be inconsistent with the requirements of the agreement on implementation of article VI of GATT, 1994 and other covered agreements.

Examination by the Authority

- 27. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to

respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information.

I. CHINA PR

28. The following producers and exporters from China filed the prescribed questionnaire responses:

1. M/s Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd,
2. M/s Amino Chem-(HK) Co., Ltd.

29. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The exporter/ producer of the subject goods from China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

30. The Authority observes that none of the Chinese producers have claimed for market economy treatment in terms of Para 8(3) of Annexure 1 to the Anti- Dumping Rules. Therefore, the Designated Authority is left with no alternative but to determine normal value estimated on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin.

31. In view of the above, the normal value for the subject products imported from China PR into India has been determined on "any other basis" by considering best available information with regard to cost of production and after reasonable additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. The normal value has been constructed considering consumption of major raw materials as per best available information, international prices for major raw materials, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry. Further, reasonable profit @ 5% of cost of sales has also been added for constructing Normal Value.

i. Export price in case of M/s Zhejiang Hongsheng and M/s Amino Chem HK

32. During the POI, M/s Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd, has exported subject goods to India directly and through their related party M/s Amino Chem-(HK) Co., Ltd., as per the details mentioned in Appendix 2 of the Questionnaire response. The exporter has claimed adjustment on account of inland freight, overseas freight, marine insurance, credit cost, Bank charges etc. and the same have been accepted after necessary verification.

ii. Export Price for all other producers and exporters

33. For other producers/ exporters from China who have not participated / cooperated in this investigation, the Authority determined the export price on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules.

Producer	Exporter	Constructed Normal Value USD/MT	Net Ex-Factory Export Price USD/MT
M/s Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd	M/s Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd / M/s Amino Chem-(HK) Co., Ltd.	***	***

II. JAPAN

34. One producer namely M/s Sumitomo Chemical Co., Ltd has filed their response along with the response from their unrelated/unaffiliated exporters:

1. M/s East West Corporation
2. M/s Sumika Chemtex Co. Ltd.
3. M/s B R Chemicals Co. Ltd.
4. M/s Inabata & Co. Ltd.

i. Normal Value in case of M/s. Sumitomo Chemicals Co. Ltd

35. The questionnaire response filed by the producer/exporter has been examined and verified to the extent possible. M/s. Sumitomo Chemicals Co. Ltd. has sold majority of subject goods in the domestic market directly. A limited quantity of sales was also made in the domestic market through related companies, i.e. M/s Inabata & Co. Ltd. and M/s. Sumika Chemtex Co. Ltd in the ordinary course of trade. The producer has provided the details of the same in relevant Appendices of their response. The sales were put to profitability test and it was noted that less than 80% transactions of the total domestic sales are profit-making. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based on profitable sales data only. The Normal value of the exporter is determined as mentioned in the table below.

ii. Export price in case of M/s. Sumitomo Chemicals Co. Ltd.

36. The producer has exported the subject goods to India through two channels, i.e. directly to the Indian customer as well as through other unrelated exporters. The exports were made on CIF terms and adjustments claimed by the producer-exporter for their direct exports are on account of inland freight, overseas freight, insurance cost, credit cost, bank charges and other applicable expenses. The same have been verified and accepted to the extent found correct. The Net Export price of the exporter for the direct exports so determined is as below.

iii. Export price in case of M/s. B. R. Chemicals and M/s. East West Corporation

37. During the POI, M/s B.R. Chemicals Co. Ltd. has exported subject goods through M/s East West Corporation which were procured from M/s Sumitomo Chemicals Co. Ltd. The details of the said exports have been submitted in Appendix 2 filed independently by each of the above trader/exporter. The exports were made on CIF terms and adjustments claimed by the trader/ exporter for these exports are on account of inland freight, overseas freight, insurance cost, bank charges, credit cost, commission, SG&A, Profit and other applicable expenses. However, the producer and exporter are not related therefore the Authority accepted the sales price from the producer to exporter and verified the same for the applicable adjustments. The export price for the exporter is determined as mentioned in table below.

iv. Export Price for all other producers and exporters

38. For other producers/ exporters from Japan who have not participated / cooperated in this investigation, the Authority determined the normal value and export price on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules.

Producer	Exporter	Normal Value USD/ MT	Net Export Price USD/ MT
M/s Sumitomo Chemicals Co. Ltd.	M/s Sumitomo Chemicals Co. Ltd / M/s B.R. Chemicals Co. Ltd & M/s East West Corporation	***	***

III. DUMPING MARGIN

39. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing constructed normal value and net export price at ex-factory level of the subject goods. The table below shows the dumping margin values for cooperative producers/exporters.

S No.	Producer	Exporter	Normal Value		Net Export Price		Dumping Margin			
1	China		USD/MT	INR/MT	USD/MT	INR/MT	USD/MT	INR/MT	%	Range
1a	Zhejiang Hongsheng Chemical Co. Ltd.	Zhejiang Hongsheng Chemical Co. Ltd./ Amino Chem (HK) CO. Ltd.	***	***	***	***	***	***	***	40-50
1b	Any Other	Any Other	***	***	***	***	***	***	***	70-80
2	Japan									
2a	Sumitomo Chemicals Co. Ltd.	Sumitomo Chemicals Co. Ltd./ B.R. Chemicals Co. Ltd., & East West Corporation	***	***	***	***	***	***	***	15-25
2b	Any Other	Any Other	***	***	***	***	***	***	***	25-35

40. It is seen that the dumping margin for the subject goods is more than de-minimus for imports for all the exporters from the subject countries.

F. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**Submissions made by the Domestic Industry**

41. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- Imports of the product under consideration have shown increase over the years with a significant increase in POI. Imports have also shown increase in relation to production and consumption in India;
- The injury to the domestic industry is because of dumped imports. None of the interested party has provided any evidence on record as to how the domestic industry has suffered injury due to factors other than dumping from the subject countries. Mere unsubstantiated statements have been made.
- Market share of subject countries in demand is significant. Market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year. The same is due to significant imports from subject countries;
- With reduction in the prices by the foreign producers, the only choice available to the Indian

- producer is to either realign their prices with the changes in the import prices or to lose orders and hence the market share;
- v. Domestic industry prices, reflect the effect of the prices that are being offered by the importers in the domestic market;
 - vi. The price underselling and price undercutting is positive and substantial. Further, the Domestic Industry is suffering from price depression as they are not able to increase its prices to reasonable terms. The main reason for this is high volume of imports from subject countries that too at dumped and injurious prices.
 - vii. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent.
 - viii. The decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the import volume at non-remunerative prices from subject countries.
 - ix. The capacity figures as mentioned by the opposing parties is incorrect and baseless. They seems to have picked up the figures from environmental clearances obtained for the plant which is actually not the actual capacity or production figures. As regards, the depreciation of plant, the same has been duly accounted in the calculations made by the Authority.
 - x. The increase in selling price was lower than the increase in cost of production and thus the dumped imports are creating price suppression effect on the domestic industry.
 - xi. The domestic industry has suffered material injury in connection with dumping of subject goods from subject countries. The dumping margin calculated is also substantially high. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue.

Submissions made by the opposing interested parties

42. The following are the injury related submissions made by the opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority.
 - i. The Domestic Industry is not suffering any material injury from the alleged dumped imports, on the contrary, the performance of Domestic Industry has improved throughout the injury investigation period. From 2012-13 to 2013-14, both imports and domestic sales increased at the same rate, therefore, no correlation can be established with respect to the imports and the performance of the domestic industry. Most of the criteria presented by the Petitioner at Proforma IVA of the Petition reflect an improvement over the injury period.
 - ii. There is no causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry is self-inflicted. Injury to domestic industry is on account of outdated and inefficient process used by them to manufacture the subject goods.
 - iii. The petitioner deliberately failed to address a number of critical issues which had an impact on the performance of the domestic industry independently from the imports from the subject countries.
 - iv. There is no price undercutting, price suppression and depression and therefore, the claim of Domestic Industry of any injury on account of imports from subject countries should be rejected;
 - v. The Injury Margin that is calculated by the Petitioners cannot be verified at all by the Exporters due to insufficiency in the data/information provided. The Hon'ble Designated Authority is requested to ensure that the Petitioner has fulfilled all the conditions as laid out at Annexure II and Annexure III of the AD Rules.
 - vi. The plant started production in 2003. As per legal filings made by the Petitioner, the installed capacity at the time was 5520/MT and continues to be the same ever since. Therefore, the plant is (1) of 5520MT capacity and is (2) fully depreciated and the NIP should take the same into consideration.
 - vii. It cannot be said that the Petitioner has been forced to sell at a price which did not allow it to cope with the changing cost over the injury period Along with the increase in selling price, the

Petitioner has also experienced stable costs over the injury period, whereby prices have increased notably more than cost.

- viii. The Petitioner's focus has been more on Export market rather than domestic market because of higher sales realisation in case of exports, despite huge Demand-Supply gap, which clearly demonstrates that export is a preference and not a compulsion for the petitioner.
- ix. They have a sales channel which is also highly uncompetitive. They are selling at low prices in order to cover the cost of their distribution network. Except for a few large clients, the bulk of their business is done through such channels.
- x. The declining profitability appears to have absolutely no correlation with any of the price or cost parameters of the Petitioner. If the profitability of the Petitioner was being negatively affected by imports from subject countries, any increase in the landed price would also increase the profitability of the Petitioner. The very fact that profits are increasing in the period where dumping (with declining import prices) is alleged to have taken place also evidences a severe breach in causality. It would clearly be seen there is evidently a blatant error in the figures of profit/loss. If profit/loss per unit is negative, total profit/loss cannot be positive.
- xi. There is a significant difference in imports as reported by petitioner and as per DGCI&S.
- xii. According to the Environmental Impact Assessment Report, 2016, it is clear that the Petitioner has misrepresented its capacity figures.
- xiii. There is no reason for capital employed to go down drastically when there are capital investments made and increase substantially in the next year, in complete disproportion to the investment made.
- xiv. Petitioner claims that it has invested capital in capacity expansion, there is no evidence of such capacity expansion in any of their legal filings made with the relevant government authorities under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Examination by the Authority

43. The impact of the dumped imports on the domestic industry is to be examined in terms of Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties during the course of the present investigations and considered relevant by the Authority. The Authority has computed the non-injurious price in accordance with Annexure 3 to the Anti-dumping Rules and the established practices of the DGAD.
44. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II of the Rules supra. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S.

i. Assessment of Demand

45. For this purpose, demand or apparent consumption of the subject goods in India is taken as the sum of domestic sales (merchant as well as captive) of the Indian producer and imports from all sources.

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Imports from Subject Countries	MT	2,470	2,889	3,226	3,343
2	Imports from Other Countries	MT	372	425	92	177
3	Total Sales of Domestic Industry in India	MT	1,095	1,557	886	1,169
i	Merchant Sale of DI	MT	965	1,100	674	953
ii	Captive Sales of DI	MT	130	457	212	216

4	Sale of other Indian Producers	MT	0	0	0	0
5	Total Demand	MT	3,937	4,871	4,204	4,689

46. The Authority notes that the total demand in India has increased in POI as compared to the base year, it is noted that during 2013-14 there was a hike in demand which is also translated in increased domestic sales.

ii. Volume Effect of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

47. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import of the subject goods from the subject countries has been analyzed as under:

S. No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Imports from China	MT	549	1,433	1,030	1,107
1a	Trend	Indexed	100	261	187	201
2	Imports from Japan	MT	1,921	1,456	2,196	2,236
2a	Trend	Indexed	100	76	114	116
3	Imports from subject countries	MT	2,470	2,889	3,226	3,343
3a	Trend	Indexed	100	117	131	135
4	Imports from other countries	MT	372	425	92	177
5	Total Imports	MT	2,842	3,314	3,318	3,519
6	Domestic sales	MT	1,095	1,557	886	1,169
6a	Trend	Indexed	100	142	81	107
7	Total Demand	MT	3,937	4,871	4,204	4,689
7a	Trend	Indexed	100	124	107	119
8	Share of Subject countries' imports					
8a	in Total imports	%	87	87	97	95
8b	in Demand	%	63	59	77	71
9	Share of Other Countries' imports in Demand	%	9	9	2	4
10	Share of DI in Demand	%	28	32	21	25

48. It is noted that imports of the subject goods from the subject countries in absolute terms have increased consistently during the entire injury period and POI. The share of imports of subject countries in total imports is 95% during the POI which is significant. Further, the imports from China have doubled during POI as compared to the base year and imports from Japan have shown growth of 16% during POI as compared to base year. The total imports from subject countries have increased to the extent of 35% in POI as compared to base year. The share of imports in relation to demand have increased during the POI as compared to the base year, however, there is a decline when compared to the previous year. The DI has more or less maintained their share with a peak in 2013-14.

iii. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

49. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from subject countries.

a) Price Suppression and Depression

50. In order to determine whether the dumped imports (value taken from DGCI&S) are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were compared as below:

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Landed Value of imports	Rs./MT	309,154	345,788	356,694	315,081
1a	Trend	Indexed	100	112	115	102
2	Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	108	114	110
3	Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	102	109	102

51. From the above, it is noted that the cost of sales of Domestic Industry for subject goods has marginally increased in POI as compared to base year with a hike during 2014-15, on account of increase in raw materials and fuel prices. As for the selling price of the domestic industry, it is noted that the same has increased but it is below the cost of sales during the entire injury period. Further, it is noted that the landed value of the subject imports is below the cost of sales of the DI. This affirms the claim of the Domestic Industry that they are always under price pressure from the dumped imports and are forced to match the prices of the lowest import in order to retain their leftover market share. It is noted that the landed value of imports from the subject countries decreased during POI as compared to the previous years (2013-14 & 2014-15). From the aforesaid, it is apparent that the domestic industry is feeling the effect of price suppression / depression.

b) Price Undercutting

52. The Domestic Industry has stated that they were under continued pressure from the exporters of subject countries and kept its selling price lower than the lowest of the imports in order to retain their domestic market share. The landed price of imports as obtained from DGCI&S have been compared with the selling price as below and it is noted that the price undercutting is negative.

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Landed Value of imports	Rs./MT	309,154	345,788	356,694	315,081
2	Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	108	114	110
3	Price Undercutting	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)

3a	Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	(***)
3b	Range	Indexed	(15)-(5)	(15)-(5)	(15)-(5)	(10)-(1)

c) Price Underselling

53. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of alleged dumped imports from subject countries. The analysis has been undertaken on basis of NIP of domestic industry and the landed value of the imports of the cooperative exporters from China and Japan, who account for the total imports from the respective subject countries.

S.No.	Particulars	Unit	China	Japan
1	NIP	Rs/MT	***	***
2	Landed value of imports	Rs/MT	***	***
3	Price underselling	Rs/MT	***	***
3a	Price underselling	%	***	***
3b	Price underselling	Range	10-20	10-20

54. It is noted from the above table that the domestic industry has suffered price underselling on account of imports of the subject goods from the subject countries.

iv. Economic Parameters of the Domestic Industry

55. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments etc.
56. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a) Market share:

57. The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry and subject countries are as below:

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Total Domestic Sale (including captive sales)	MT	1,095	1,557	886	1,169
1a	Trend	Indexed	100	142	81	107
2	Imports from Subject Countries	MT	2,470	2,889	3,226	3,343
3	Imports from Other Countries	MT	372	425	92	177
4	Total Imports	MT	2,842	3,314	3,318	3,519
5	Total Demand	MT	3,937	4,871	4,204	4,689
5a	Trend	Indexed	100	124	107	119
6	Market share in Demand					

6a	Of Domestic Sales	%	28	32	21	25
6b	Of Imports from Subject countries	%	63	59	77	71
6c	Of Imports from Other Countries	%	9	9	2	4

58. It is seen that the imports of the subject goods from subject countries have increased consistently during the entire injury period. It may also be noted that market share of domestic sales has marginally decreased during POI as compared to the base years whereas the share of imports from subject countries has increased.

b) Profitability:

59. The petitioner has stated that they have suffered losses during the entire injury period. The selling price has increased though it has been consistently below the cost of sales during the entire injury investigation period and POI.

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
1a	Trend	Indexed	100	102	109	102
2	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	108	114	110
3	Profit/Loss	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
3a	Trend	Indexed	(100)	(135)	(81)	(136)

60. From the above, it is noted that the cost of sales of Domestic Industry for subject goods has marginally increased in POI as compared to base year with a hike during 2014-15, on account of increase in raw materials and fuel prices. As for the selling price of the domestic industry, it is noted that the same has increased but it is below the cost of sales during the entire injury period, therefore, DI is suffering losses during the entire period.

c) Return on Investment:

61. The return on investment has seen consistently negative trend during the entire injury period as can be seen from the table below:

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Profit per unit	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
1a	Trend	Indexed	100	83	91	78
2	ROCE	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
2a	Trend	Indexed	100	116	48	61

d) Production and Capacity Utilization:

62. Domestic Industry has marginally increased their capacity during 2013-14 (mainly on account of debottlenecking) and thereafter remained the same. The production of the Domestic Industry has consistently increased which is largely due to the fact that the demand has increased in the country. Further, the capacity utilization, has increased consistently during the entire injury period.

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Capacity	MT	2,160	2,280	2,280	2,280
2	Production	MT	1,607	1,941	1,967	2,055
3	Capacity utilization	%	74	85	86	90

e) Sales Volumes:

63. The sales volume of the Domestic Industry has shown a marginal increase in POI as compared to base year with a high peak in 2013-14 and dip in 2014-15. It has further been stated by the petitioner that they have not been able to increase the sales quantity despite increase in demand, which they have assigned to the fact that exporters from the subject countries are adopting dumping techniques. They had to undertake exports as they are getting better remunerative prices in the export market as compared to prices in the domestic market. The petitioner has claimed that they would prefer a larger share in the domestic market at remunerative prices particularly as the demand in India is consistently increasing.

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Domestic Sales (Merchant Sales)	MT	965	1100	674	953
1a	Sales Price – Domestic	Rs. / MT	***	***	***	***
1b	Trend	Indexed	100	108	114	110
2	Captive Sales	MT	130	457	212	216
2a	Sales Price- Captive	Rs/MT	***	***	***	***
2b	Trend	Indexed	100	107	102	101
3	Export Sales	MT	455	420	1088	815
3a	Sales Price – Export	Rs./ MT	***	***	***	***
3b	Trend	Indexed	100	113	108	114

64. It is noted that the export sales have almost doubled during POI as compared to base year and the same are at better remunerative prices as compared to domestic sales. It clearly indicated that Domestic Industry is efficient and subject goods are of comparable quality enabling them to create an export market and also realizing good prices. Further it is noted that their domestic sales (merchant and captive) are around 60% of total sales of the DI even though the selling price for merchant sales in India is lower than the export prices and also the prices at which the subject goods are being captively consumed (cost of production minus administrative expenses – as per the applicable transfer pricing laws). However, the present injury analysis is only based on the injury caused by the dumped imports for merchant sales.

f) Inventories:

65. It is noted that the average inventory of the Domestic Industry in ideal situation is for 4-5 days but the same is on higher side with an increase in POI.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	55	167

g) Productivity, Employment and Wages:

66. It can be seen from the table below that total production as well as productivity in terms of production per employee has increased consistently during the entire injury period. It is also noted from the table that the number of employees during the POI has remained at the same level as that of base year inspite of

increase in production. The domestic industry has claimed that this is because they have to cut the costs to match the prices offered by the exporters. However, the wages paid by them have increased during the POI when compared to the base year and previous year. The position with regard to production, employment and wages is as follows:

S.No.	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
1	Production	MT	1,607	1,941	1,967	2,055
1a	Trend	Indexed	100	121	122	128
2	Employees	Nos.	***	***	***	***
3	Production/employee	MT	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	124	126	128
4	Wages/employee	Rs	***	***	***	***
4a	Trend	Indexed	100	106	99	110

67. The increase in wages is a natural cause and not attributable to alleged dumping. In fact the number of employees remaining the same while there is an increase in production indicates that they have become more efficient which is further indicative by the numbers that the production per employee has increased.

h) Magnitude of Dumping:

68. Magnitude of dumping has been determined in earlier paras on the basis of comparison of normal value/ constructed normal value of the exporter with their net export prices at the level of ex-factory and is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. In the present case the dumping margin determined against subject countries is above *de minimis*.

i) Growth

69. The growth of the domestic industry cannot be termed as positive. Profits as well as ROCE remained negative during the entire injury period and POI despite a significant increase in demand for the subject goods. The domestic industry has contended that with increase in demand, the domestic industry had expected growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not been able to achieve the same due to the presence of the dumped imports from subject countries as is apparent from a positive underselling and positive price suppression and depression.

j) Factors Affecting Domestic Price

70. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. The import prices from subject countries directly affect the prices of the domestic industry in the domestic market. It is also noted that the landed value of subject goods from subject countries are below cost of sale and non-injurious price of the domestic industry. Further, landed value from subject countries had suppressed / depressed the prices of the Domestic Industry causing financial losses to DI. The imports of the product under consideration from countries other than subject countries are not injuring the domestic industry as the prices offered by these countries are significantly higher. Demand for the product is showing an increasing trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the domestic industry. It is thus reasonably evident that the dumped goods from subject countries are responsible for the depressed and suppressed prices of the domestic industry.

V. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

71. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-dumping have

[illegible]

	Ltd	Ltd / M/s B.R. Chemicals Co. Ltd & M/s East West Corporation								
2b	Any Other	Any Other	***	***	***	***	***	***	** *	25-35

H. POST DISCLOSURE COMMENTS

80. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

Submissions made by the Domestic industry

81. The Domestic Industry filed comments to the Disclosure statement beyond the prescribed time limit and therefore, the same have not been considered.

Submissions made by the opposing interested parties

82. The submissions of various opposing interested parties are summarized as follows:

- i. The deadline for submissions on Disclosure statement is unreasonably short to appropriately respond and defend the interests sufficiently. Moreover, this is inconsistent with article 6.9 of the AD agreement.
- ii. The technology issues raised by a Japanese company and other interested parties have nothing to do with domestic like product. The arguments were made with regard to the insufficiency of the process used by the Domestic Industry, thus leading to a self-inflicted injury and a breach in causal link. The production process of the domestic industry being inefficient, leads to their costs being unnecessarily high, which in turn has led to self-inflicted material injury. This argument does not pertain to the scope of the product under consideration, but rather the factors of non-attribution as mentioned in paragraph (v) of Annexure II to the AD Rules.
- iii. The exclusion of USA due to the imports being used captively is not only void of any legal basis but it is also discriminatory. Irrespective of whether the product imported for end use, captive use or trade, as long as the imports for a country were more than 3% the country should be considered as a subject country.
- iv. The Professor and the Petitioner have completely ignored the production of Resorcinol tar ("Reso-tar") from the Petitioner's final distillation process as a by-product. The fact that the Professor has not mentioned Reso-tar as a by-product in the Petitioner's production process highlights the deficiency in its analysis with respect to Resorcinol's production process and thus his comments with respect to the same must be completely disregarded. The by-products that are produced through the Petitioner's technology cannot be easily commercially sold.
- v. The Petitioner vide its letter dated December 5, 2017 has attempted to make false assertions with respect to the closure of Indspec by blaming the closure on expansion of Sumitomo Chemical Co., Ltd. The Exporters have previously submitted that in March 2017, Indspec announced closure of plant because of inefficiencies in the manufacturing process compared to its global competitors.
- vi. The Petitioner's submissions that the imports are being used for captive consumption to produce downstream product is false. The imports have been made by them from Japan during 2013-14 and later from other country to fill in the gaps in their own supply as they do not have the ability to produce 1,3 Cyclohexanedione, Resoform P-18, Resoform P-19 and Resoform P-20, which require Resorcinol as a raw material.
- vii. There is absence of causal link as the inefficiency of the domestic producer does not prove that the price of the Domestic products was forced to be lower due to dumping of imported products. The production amount and capacity utilization and productivity of the Domestic Industry have increased during the POI. Any injury caused to the domestic industry is not on account of imports from the Subject Countries rather due to its own technological inefficiencies and other extraneous issues.

- viii. The figures (the trend) provided therein for cost per unit and selling price per unit, cannot be exactly the same.
- ix. The cost of the Petitioner is heavily inflated due to its inefficient production technology. This leads to an unnecessarily high production cost and resultantly, an inflated Non Injurious price. If the NIP is inflated due to an inefficient technology, then obviously there would be underselling in the analysis.
- x. The domestic industry has not established that the imports are suppressing or depressing the domestic prices. There is negative undercutting from the subject countries in the present investigation. If a market is price-oriented, as appears to be the claim of the Petitioner, then the lowest price sets the price trends in the market. In the present case, the price trends are clearly being set by the Petitioner, whereby there can be no question of price depression or even price injury.
- xi. The dumping margin and injury margin calculated by the Petitioner is inconsistent and is relying on the Petitioner's so-called own cost, which is estimated to be far deviating from global standard of the product under consideration.
- xii. The Authority has not provided any grounds for cumulative assessment.
- xiii. Demand for the product under consideration in India is higher than production and capacity. Imports are coming to fill the demand supply gap.
- xiv. The Authority for the purposes of calculating the normal value of M/s Sumitomo Chemical Co., Ltd., has only considered profitable sales as it has concluded that M/s Sumitomo Chemical Co., Ltd. failed to make more than 80% of its total sales in the home market profitable. In fact more than 80% of the sales in the domestic market were indeed profitable. The Authority has not provided any reason as to why they disregarded the other non-profitable transactions.
- xv. The Authority has not elaborated on how it has arrived at 22% for computing a reasonable return on capital employed 22%. The Authority is requested to provide the parameters that it has taken into consideration for arriving at 22%.
- xvi. Authority is humbly requested to recommend only a reference price form of anti-dumping duty in the event that positive injury margin, positive dumping margin and causal link is established. There are only three producers in the world for Resorcinol which leads to a limited supply in India thus making it difficult for importers and users to obtain the product.

Examination by the Authority

83. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs, however for the sake of the clarity of the submissions they are addressed as below:
- i. As regards the timeline for submissions of comments on Disclosure statement, a reasonable time of 7 days was given to all the interested parties. The time is sufficient to respond as the interested parties are required to only point out discrepancies or the missing data/information/submissions if any. The comments received within the prescribed time period have been duly addressed.
 - ii. As regards the price effect analysis, the Authority notes that the purpose of the Disclosure statement under Rule 16 of the AD Rules is to inform all the parties of the essential facts under consideration. The Authority is not mandated to disclose its determination at the stage of Disclosure under Rule 16 of the AD Rules. It is a penultimate stage, and the purpose of the disclosure statement is that all the parties should come to know as to what are the essential facts, information/data before the Authority which has been submitted by various interested parties and collected by the Authority upto the stage of issuing the Disclosure Statement which would lead to form the basis for framing and firm up the Authority to its final determination in the final finding. If from the contents of the disclosure statement any interested party thinks that some facts/information/data of importance and relevance to the investigation has been missed out or left out or not properly considered by the Authority, the interested parties can bring the same to the notice of the Authority for consideration on merits while forming its final opinion in the final finding.

- iii. As regards the calculation of NIP, the Authority notes that NIP and cost of production has been determined as per the Rules and the practices followed in the Directorate. The cost of production calculated for the exporter in Japan was shared with them and also discussed in detail with the legal representative of the exporter.
- iv. The allegation of exporter regarding inefficient process and technology of the DI has been re-examined and it is found that their submission is not correct as the by-product claimed by the exporter is produced in very small quantity (to the extent of 3% only) and the sales of the same have already been appropriately accounted in the NIP. Further, the Authority notes that the technology used by DI is not inefficient and hence the relevance of the argument for PUC as well as causal link on that ground is baseless.
- v. The examination of information furnished by the petitioner had revealed that they are manufacturing the downstream products by consuming Resorcinol as raw material which is also evident by their own captive consumption of the subject goods which was duly reflected in their books of accounts submitted to the Authority.
- vi. The normal value for Japan has been determined as per the detailed information provided by the co-operative exporter, whereas, for China the normal value has been constructed and the reasons have been detailed in above mentioned paras.
- vii. The information furnished by M/s. Sumitomo Chemicals Co. Ltd., was duly examined and verified to the extent possible and the cost of production was worked out as per the Rules. The domestic sales were put to 80/20 test and thereafter the Authority has determined the normal value based on profitable sales transactions.
- viii. As regards to the non-inclusion of USA in the present investigation it is noted that this fact was examined by the Authority at the time of initiation of the investigation as detailed in the relevant para above. Further, the single manufacturing facility in USA has already closed down during the course of the investigation, as was admitted by all the interested parties during oral hearing. The impact of imports from USA has no bearing on the final findings and is only an academic issue.
- ix. The numbers mentioning trend for cost of sales and selling price have been rectified as it was a typographical error, however, the absolute numbers were correct and there is no implication on the outcome of the investigation.
- x. As the criteria mentioned in Para (iii) of Annexure –II of the Rules were applicable in the present case, the cumulative assessment for injury analysis has been correctly undertaken by the Authority.

J. CONCLUSIONS

84. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value, resulting in dumping.
- ii. The Domestic Industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
- iii. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

85. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the downstream products and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti- dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the Domestic Industry. On the contrary, imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the Domestic

Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

L. RECOMMENDATION

86. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the Domestic Industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries for a period of three years only in the form and manner described hereunder.

87. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of 3 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 8 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 8. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

Duty Table

S.No.	Tariff Item*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (in USD)	UOM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29072100	Resorcinol	China PR	China PR	Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd	Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd / Amino Chem-(HK) Co., Ltd.	5461	MT
2	29072100	Resorcinol	China PR	China PR	Any combination other than Column 1	Any combination other than Column 1	5461	MT
3	29072100	Resorcinol	China PR	Any	Any	Any	5461	MT
4	29072100	Resorcinol	Any	China PR	Any	Any	5461	MT
5	29072100	Resorcinol	Japan	Japan	Sumitomo Chemicals Co. Ltd	Sumitomo Chemicals Co. Ltd / B.R. Chemicals Co. Ltd & East West Corporation	5461	MT
6	29072100	Resorcinol	Japan	Japan	Any combination other than Column 4	Any combination other than Column 4	5461	MT
6	29072100	Resorcinol	Japan	Any	Any	Any	5461	MT
7	29072100	Resorcinol	Any	Japan	Any	Any	5461	MT

*Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC

88. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority